● वर्ष-3
● अंक-288
रायपुर, शुक्रवार
12 जुलाई 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› कम से कम खर्च में घूमने के लिए...

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय वित्त आयोग से मांगा छत्तीसगढ़ के लिए विशेष अनुदान

राज्य में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण रेल, सड़क, दूरसंचार, परियोजनाओं की बढ़ जाती है लागत

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज छत्तीसगढ़ के प्रवास पर आए 16वें वित्त आयोग के साथ बैठक में राज्य की विशेष परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ को विशेष अनुदान देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ नवोदित राज्य है, जो जनजातीय बहुल, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों से घिरा एवं माओवाद प्रभावित है। छत्तीसगढ़ को विकसित राज्यों की बराबरी में लाने के लिए अधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी। बैठक में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया, उप मुख्यमंत्री अरूण साव और विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल, जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, वित्त आयोग के सदस्य अजय नारायण झा, श्रीमती एन्नी जार्ज मैथ्यू, डॉ. मनोज पांडा, डॉ. सौम्यकांति घोष, सचिव श्री रित्विक पांडे सहित दल के सदस्य उपस्थित थे।

बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं, साथ ही माओवाद पर अंकुश लगाने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इन क्षेत्रों में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अधोसंरचना विकास के कार्यों में अतिरिक्त व्यय भार आता है। नियद नेल्लानार योजना के अंतर्गत इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं।

अधोसंरचना विकास के लिए केन्द्र से और अधिक संसाधन मिलेः ओपी

वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने राज्य के वित्तीय परिदृश्य पर प्रस्तुतीकरण देते हुए कहा कि नवा रायपुर को ग्रीन स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां अधोसंरचना विकास के लिए केन्द्र से और अधिक संसाधन मिलने चाहिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ निर्धारित मापदंडों के अनुसार वित्तीय अनुशासन का पालन कर रहे हैं और आगे भी इसे जारी रखेंगे। कर प्रणाली में आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर लीकेज को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा केन्द्र और राज्यों के बीच करों के बटवारें के मापदंडों के बारे में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उप मुख्यमंत्रियों और मंत्रिगणों ने भी वित्त आयोग के समक्ष अपने विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी देते हुए अधिक संसाधन उपलब्ध कराने का आग्रह किये।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि केंद्रीय वित्त आयोग से राज्य को अधिक वित्तीय सहायता की अनुशंसा की जाती है, तो निश्चित ही पिछड़े इलाकों में लोकहित के कार्यों को बड़े पैमाने पर किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि देश तेजी से आर्थिक महाशक्ति बन रहा है और इसके लिए छत्तीसगढ़ भी पूरी मेहनत से काम कर रहा है। विकसित भारत के साथ ही विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण हम करेंगे। हमारी अपेक्षा है केंद्रीय वित्त आयोग छत्तीसगढ़ के हमारे विजन को अमल में लाने के लिए अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण रेल, सड़क, दूरसंचार, ऊर्जा, सिंचाई की परियोजनाओं की लागत एवं समय-सीमा में वृद्धि के कारण हमें अतिरिक्त व्यय भार वहन करना पड़ रहा है। खनन गतिविधियों के कारण पर्यावरण को होने वाली क्षति और लोगों पर स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों से निपटने के लिए हमें अतिरिक्त धनराशि खर्च करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि जीएसटी खपत एवं गन्तव्य आधारित कर प्रणाली के कारण खनन गतिविधियों का वास्तविक लाभ छत्तीसगढ़ को न मिलकर उन राज्यों को मिल रहा है.

विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए सर्विस सेक्टर पर ध्यान देने की जरूरतः पनगढ़िया

केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविन्द पनगढ़िया ने छत्तीसगढ़ की आर्थिक प्रगति की रफ्तार की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रदेश में तेजी से प्रगति हो रही है। नवा रायपुर को बहुत सुन्दर और व्यवस्थित तरीके से बसाया गया है। छत्तीसगढ़ बहुत ही सुन्दर राज्य है। विकसित भारत एवं विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स पर जोर देना होगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में राजकोषीय स्थिरता के साथ आर्थिक वृद्धि एवं सामाजिक सूचकांकों में तेजी से सुधार हुआ है। छत्तीसगढ़ एक नवोदित एवं तेजी से बढ़ता राज्य है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने के संबंध में कहा कि यहां का सबसे बड़ा संसाधन मानव शक्ति है। जिनको मैन्यूफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए स्किल्ड बनाना होगा।

मोदी सरकार को उमर अब्दुल्ला की चुनौती, कहा-

आतंकवादियों के सामने न झुकें, चुनाव कराएं

जम्मू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव टालने की अटकलों का जवाब देते हुए इस बात पर जोर दिया कि सरकार को आतंकवादियों के दबाव में नहीं आना चाहिए और जम्मू-कश्मीर में लंबे समय से प्रतीक्षित विधानसभा चुनावों में और देरी नहीं करनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा, मौजूदा स्थिति उतनी गंभीर नहीं है जितनी 1996 में थी। हमारे सुरक्षा बल, पुलिस और अन्य एजेंसियां आतंकवादी हमलों से निपटने और जवाब देने में सक्षम हैं, जैसा कि कठुआ में देखा गया। हालांकि स्थिति पूरी तरह से स्थिर नहीं है। यह इतना अस्थिर नहीं है कि हम इस साल के अंत में जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं करा सकें। उमर ने कहा, हमें अपने सुरक्षा बलों पर भरोसा रखना चाहिए और अगर हम आतंकवादियों को सर्वोच्चता देना चाहते हैं तो चुनाव न कराएं। कश्मीर ने बदतर हालात का सामना किया है, लेकिन इससे जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर कभी असर नहीं पड़ा। पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 मामले पर अपने फैसले के दौरान, केंद्र सरकार और भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को सितंबर 2024 तक या उससे पहले जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया था। इसके बाद, प्रधान मंत्री और दोनों गृह मंत्री ने शीर्ष अदालत के आदेशानुसार इन चुनावों को समय पर कराने की पुष्टि करते हुए कई बयान जारी किये।

दिल्ली में इंडिया गठबंधन पूरी तरह से खत्म!

आप की आपदा में कांग्रेस के लिए अवसर की उम्मीद

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के कुछ हफ्ते बाद, राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) के बीच गठबंधन सुलझता दिख रहा है। दोनों दल विपक्षी इंडिया गुट के प्रमुख घटक हैं। चुनाव नतीजों में केंद्र में शासन करने वाली भाजपा को दिल्ली की सभी सात सीटें मिलीं। कांग्रेस ने तीन निर्वाचन क्षेत्रों - चांदनी चौक, उत्तर पश्चिम दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली - पर चुनाव लड़ा, जबकि आप ने अपने सीट-बंटवारे समझौते के तहत पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। भाजपा ने लगातार तीसरी बार दिल्ली में संसदीय चुनावों में जीत हासिल की। कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि पार्टी के तीनों उम्मीदवारों - जेपी अग्रवाल (चांदनी चौक), उदित राज (उत्तर पश्चिम दिल्ली) और कन्हैया कुमार (उत्तर पूर्वी दिल्ली) ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) को बताते हुए अपनी हार के लिए आप को जिम्मेदार ठहराया है। दो सदस्यीय तथ्य-खोज समिति ने कहा कि उन्हें अपने अभियानों के दौरान कथित तौर पर आप से सहयोग की कमी का सामना करना पड़ा। ऐसे समीक्षा पैनल का गठन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन राज्यों के लिए किया है जहां लोकसभा चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक या उससे नीचे था।

बच्चे... कितने अच्छे! भारत की आबादी कौन बढ़ा रहा है, क्या मोदी सरकार लाएगी नया कानून?

नई दिल्ली। हम में से शायद ही कोई होगा जिसने जनसंख्या पर निबंध न लिखा हो। उन सारे निबंधों में हमने यही लिखा कि जनसंख्या का बढ़ना एक चुनौती है और इस चुनौती से निपटने के लिए परिवार नियोजन आवश्यक है। ऐसे प्रोग्राम भी आते थे जिसमें परिवार नियोजन की सीख दी जाती थी। इस प्रयास का एक ही लक्ष्य होता था कि बढ़ती जनसंख्या को किसी तरह से काबू किया जाए। एक और खास बात ये है कि वो हिन्दुस्तान ही है जहां शादी होती है तो सबसे शाश्वत सवाल कि खुशखबरी कब सुना रहे हो। 11 जुलाई यानी आज ही के दिन जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस के साथ ही बहस तेज हो गई है कि देश की आबादी कौन बढ़ा रहा है? क्या कोई जानबूझकर जनसंख्या बढ़ा रहा है। क्या ज्यादा बच्चों के पीछे कोई खास किस्म का इरादा तो नहीं है। जनसंख्या दिवस के बीच आरएसएस ने ये डिबेट शुरू की है। मुखपत्र आर्गनाइजर ने ये मुद्दा उठाया है। वर्ल्ड पापुलेशन डे डीलिंग विथ द डिमोग्राफिक डाइलिमा नाम से एक लंबा लेख लिखा गया है। बढ़ती मुस्लिम आबादी पर आरएसएस का विचार पहले से ज्यादा आक्रमक दिखा। इस लेख में टीएमसी के नेता जेसीबी के शरिया सजा और ममता बनर्जी की प्रो मुस्लिम राजनीति का भी जिक्र किया गया है।

प्रमुख समाचार

स्थानांतरण की आड़ में शिक्षकों का अटैचमेंट, हाईकोर्ट ने किया निरस्त

बिलासपुर। स्थानांतरण की आड़ में शिक्षकों के किए गए अटैचमेंट को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा डीईओ को शिक्षकों के अटैचमेंट का अधिकार नहीं है। मामले में सिंगल बेंच से याचिका खारिज होने पर शिक्षकों ने डीबी में अपील की थी। दरअसल, बस्तर क्षेत्र के शिक्षक दयानाथ कश्यप, चंद्रशेखर पांडे, दयाराम बघेल, मिरी राम देवांगन बस्तर क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में पदस्थ हैं। उन्होंने अपने अटैचमेंट को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सिंगल बेंच से याचिका खारिज होने पर उन्होंने रिट अपील दायर की। इन शिक्षकों को 14 एवं 15 मार्च 2024 को आदेश जारी कर मूल स्थान से स्थानान्तरण कर अन्य जगहों पर अटैच कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने जिला शिक्षा और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पर द्वेषवश कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा कि उनको ऐसा आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। राज्य शासन की स्थानांतरण नीति के अनुसार मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर कलेक्टर द्वारा उनका स्थानांतरण किया जा सकता है। साथ ही यह कार्रवाई चुनाव आचार संहिता लागू होने के दौरान की गई, इसलिए चुनाव आयोग से भी अनुमति लेना जरूरी था।

प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में एक पेड़ मां के नाम आज से

रायपुर। महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े की पहल से 12 जुलाई 2024 को प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में जल शक्ति से नारी शक्ति एवं एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जल शक्ति से नारी शक्ति के तहत जल संरक्षण विषय पर जन जागरूकता कार्यकम का आयोजन किया जाएगा। जिसमें महतारी वंदन योजना के लाभार्थी महिलाओं एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के हितग्राहियों को आमंत्रित करते हुए जल संरक्षण विषय अंतर्गत जल का महत्व, साफ और सुरक्षित जल का उपयोग, जल के संरक्षण के सही उपाय, जल संग्रहण की उपयोगी तकनीकों, जल स्त्रोतों के आस-पास साफ-सफाई एवं स्वच्छता का महत्व, साफ-सुथरा शौचालय के उपयोग के महत्व की जानकारी दी जाएगी। साथ ही कार्यक्रम में पौधारोपण से जल संरक्षण के विषयों पर जानकारी देते हुए जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रम में महिलाओं को जल शक्ति से नारी जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के लिए जल संरक्षण के संबंध में शपथ दिलाई जाएगी।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बिगड़ी तबीयत

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को गुरुवार को दिल्ली एम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग में भर्ती कराया गया। कमर दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल, अभी उनकी स्थिति बेहतर है। बीते दिन ही सिंह ने अपना 73वां जन्मदिन भी मनाया था। दिल्ली एम्स से मिली जानकारी के मुताबिक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आज सुबह पीठ दर्द की शिकायत के चलते पुराने प्राइवेट वार्ड में भर्ती कराया गया। उनकी हालत स्थिर है और उन्हें निगरानी में रखा गया है। एम्स की मीडिया सेल प्रभारी डॉ. रीमा दादा ने बताया कि उनकी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि 73 साल के सिंह को सुबह-सुबह भर्ती कराया गया और उन्हें ओल्ड प्राइवेट वार्ड में रखा गया है।

नीट पेपर मामलाः सीबीआई ने रॉकी को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। नीट पेपर मामले में सीबीआई ने राकेश रंजन के सहयोगी रॉकी को नालंदा (बिहार) से गिरफ्तार किया है। रॉकी पटना में सीबीआई की सक्षम अदालत के सामने पेश हुआ और उसे 10 दिनों के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले में सीबीआई ने पटना और कोलकाता समेत चार जगहों पर छापेमारी की। राकेश (रॉकी) को उसके आईपी पते और ईमेल पते के माध्यम से पता लगाने के लिए सीबीआई द्वारा उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था। अधिकारियों ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी के बाद, जांच एजेंसी ने पटना और कोलकाता में उनसे जुड़े विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली, जिससे कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। इससे पहले मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने नीट पेपर लीक मामले में नालंदा और गया से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जिन दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें से एक नीट-यूजी अभ्यर्थी सनी है जो नालंदा का रहने वाला है और दूसरा एक अन्य अभ्यर्थी रंजीत कुमार का पिता है जो गया का रहने वाला है। अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने अब तक बिहार एनईईटी-यूजी पेपर लीक मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया है.

बिहार विस चुनाव पर प्रशांत की नजर गांधी जयंती लॉन्च करेंगे पार्टी

पटना। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर अपनी राजनीतिक पार्टी - जन सुराज - लॉन्च करेंगे। यह घोषणा करते हुए, जन सुराज संयोजक ने हाल ही में कहा कि वह पार्टी मामलों को संभालने के लिए 21 नेताओं का एक पैनल स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं। किशोर पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि उनकी पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस साल जनवरी में, जाने-माने रणनीतिकार ने कहा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनके संगठन जन सुराज द्वारा समर्थित एक मंच द्वारा अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) श्रेणी के कम से कम 75 लोगों को मैदान में उतारा जाएगा। किशोर ने दावा किया कि राज्य में सत्तारूढ़ दलों द्वारा ईबीसी समुदाय के लोगों का हमेशा शोषण किया गया है। उन्होंने पटना में एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में आप पहली बार ईबीसी वर्ग के कम से कम 75 लोगों को एक मंच से चुनाव लड़ते देखेंगे। 2 अक्टूबर, 2022 को किशोर ने अपने जन सुराज अभियान के तहत पश्चिम चंपारण जिले से बिहार में 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू की।

बिम्सटेक के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में बोले जयशंकर

मिलकर चुनौतियों का सामना करें-समाधान खोजें

नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को सात पड़ोसी देशों के संगठन बिम्सटेक के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करते हुए कहा कि यह संगठन भारत के लिए पड़ोसी पहले, एक्ट ईस्ट और सागर दृष्टिकोण को जोड़ने का जरिया है। बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) के साथ रणनीतिक जुड़ाव को स्पष्ट करते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत के व्यापक भू-राजनीतिक ढांचे में पड़ोसी पहले, एक्ट ईस्ट नीति और सागर दृष्टिकोण बेहद अहम हैं।

उन्होंने कहा, हम पिछली बार इसी तरह की बैठक में पिछले साल जुलाई में बैंकॉक में मिले थे। उसके बाद से बिम्सटेक की गतिविधियों को गहरा और व्यापक बनाने के हमारे प्रयासों को बढ़ावा मिला है। इस साल 20 मई से बिम्सटेक चार्टर लागू हो गया है। वैश्विक और क्षेत्रीय विकास के लिए यह बेहद जरूरी है कि हम आपस में मिलकर चुनौतियों का सामना करें और समाधान खोजें। हमारे सामने क्षमता निर्माण और आर्थिक सहयोग जैसे दीर्घकालिक लक्ष्य हैं, जिन्हें काफी अहमियत मिली है। सबसे अहम बात यह है कि एक ऐसा समूह जो अपनी सदस्यता में इतना पूरक और अनुकूल है कि इससे बड़ी आकांक्षाओं को जन्म मिलेगा। इन साझा आकांक्षाओं को बिम्सटेक के महत्वाकांक्षी विजन के रूप में व्यक्त किया जाएगा।

जयशंकर ने बताया कि भारत के लिए बिम्सटेक पड़ोसी पहले, एक्ट ईस्ट और सागर दृष्टिकोण के जुड़ाव का केंद्र है। इनमें से प्रत्येक प्रयास बंगाल की खाड़ी पर विशेष ध्यान केंद्रित करके किया जा रहा है, जहां सहयोगात्मक क्षमता को लंबे समय से कमतर कर आंका गया है। हमारे सामने सहयोगात्मक क्षमतआओं को बेहतर बनाने की चुनौती है। इसके लिए हमें तीव्र बदलाव करने होंगे।

उन्होंने कहा कि हम सभी को बैंकॉक में पिछले साल हुई बैठक से काफी लाभ हुआ है। उम्मीद है, आज के प्रयासों का भी आगे लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रियों की बैठक बेहद अहम है, क्योंकि यह वर्ष के अंत में होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए मजबूत बुनियाद तैयार करती है। यहां से हमारा संदेश स्पष्ट होना चाहिए कि हम सभी बंगाल की खाड़ी के देशों के बीच सहयोग में नई ऊर्जा, नए संसाधन और नई प्रतिबद्धता को शामिल करने के लिए दृढ़ हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि दो दिवसीय सम्मेलन में कनेक्टिविटी, संस्थागत निर्माण, व्यापार और व्यवसाय में सहयोग, स्वास्थ्य और अंतरिक्ष में सहयोग, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, क्षमता निर्माण और सामाजिक आदान-प्रदान के नए तंत्रों के बारे में विचार-विमर्श किया जा रहा है।

क्या है बिम्सटेक- बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक को-ऑपरेशन (बिम्सटेक) बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसमें भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और थाइलैंड शामिल हैं। इसका मकसद बंगाल की खाड़ी से लगे देशों में तीव्र आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने और साझा हितों के मुद्दों पर समन्वय स्थापित करने के लिए सकारात्मक वातावरण बनाना है। बैंकॉक डिक्लेरेशन, 1997 के तहत इसे स्थापित किया गया।

पाकिस्तान ने भी इसमें शामिल होना चाहा था, लेकिन उसे अलग रखा गया है। शुरुआत में इसमें चार देश थे और इसका नाम बिसटेक यानी बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग संगठन था। 22 दिसंबर, 1997 में म्यांमार इसमें शामिल हो गया, तो इसका नाम बिम्सटेक हो गया था। 2004 में भूटान और नेपाल को इसमें शामिल किया गया। विदेश मंत्री जयशंकर ने आज बांग्लादेश और भूटान के अपने समकक्षों के साथ अलग-अलग बैठकें कीं। इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर फोकस किया। जयशंकर ने एक्स पर लिखा, आज शाम नई दिल्ली में बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद से मिलकर अच्छा लगा। बार-बार उच्च स्तरीय आदान-प्रदान भारत-बांग्लादेश मैत्री की ताकत को दिखाता है। हमने इसे आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। भूटान के विदेश मंत्री डीएन ढुंगयेल के साथ अपनी बातचीत पर जयशंकर ने कहा कि भारत और भूटान के बीच मित्रता और सद्भावना के अनूठे संबंधों को आगे ले जाने पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया। जयशंकर ने एक्स पर लिखा, बिम्सटेक सम्मेलन से इतर ढुंगयेल से मिलकर खुशी हुई। दोस्ती और सद्भावना के हमारे अनूठे संबंधों को आगे ले जाने पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

जयशंकर ने अपने श्रीलंका के विदेश राज्य मंत्री थरका बालासूर्या से भी मुलाकात की।

विधायक किरण देव ने की स्थाई गोंचा गुड़ी के निर्माण की घोषणा

जगदलपुर। रियासत कालीन बस्तर गोंचा महापर्व में पूरा शहर इन दिनों भक्तिमय हो गया है। गुंडिचा मंदिर-सीरासार भवन एवं श्रीजगन्नाथ मंदिर में रियासत कालीन परंपरा अनुसार विभिन्न अनुष्ठान संपन्न किये जा रहे हैं। जिसमें प्रतिदिन विभिन्न ग्रामों के श्रृद्धालुओं के द्वारा भगवान श्रीजगन्नाथ को रोजाना अमनिया भोग का अर्पण के साथ ही रोजाना हजारों श्रद्धालु श्रीजगन्नाथ के भात का प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा सत्यनारायण कथा अखंड रामायण पाठ मंडल अन्नप्राशन सहित निःशुल्क उपनयन संस्कार के अनुष्ठान जारी है। इस दौरान भगवान श्रीजगन्नाथ स्वामी के दर्शन के लिए पहुंचे जगदलपुर विधायक किरण

देव से 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के सदस्य एवं बस्तर गोंचा महापर्व के पूर्व अध्यक्ष रजनीश पाणिग्रही ने विधायक किरण देव को यह अवगत करवाते हुए बताया कि उनके महापौर के कार्यकाल के दौरान नगर निगम की ओर से प्रतिवर्ष अस्थाई नगर गोंचा गुड़ी के निर्माण की परंपरा प्रारंभ की गई थी, जो आज भी अनवरत जारी है। उन्होंने विधायक किरण देव की समक्ष स्थाई गोंचा गुड़ी के निर्माण का प्रस्ताव रखा, जिसे विधायक किरण देव ने सहर्ष स्वीकार करते हुए स्थाई गोंचा गुड़ी के निर्माण की घोषणा की है।

भाजपा के जिला कोषाध्यक्ष रजनीश पाणिग्रही ने विधायक किरण देव के द्वारा गोंचा गुड़ी के निर्माण की घोषणा के लिए आभार व्यक्त करते हुए बताया कि विधायक किरण देव स्वयं सुकमा जमींदार परिवार एवं बस्तर राज परिवार से संबंधित होने से रियासत कालीन बस्तर दशहरा एवं बस्तर गोंचा महापर्व में उनका पूरा परिवार इस परंपरा-रस्म का अभिन्न अंग हैं। जिसके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए वे हमेशा से प्रयासरत रहे हैं। इससे पहले विधायक किरण देव अपने महापौर कार्यकाल के दौरान बस्तर दशहरा पर्व के लिए मां दंतेश्वरी मंदिर के पास नगरगुड़ी का निर्माण एवं श्रद्धालुओं के बस्तर दशहरा के देखने के लिए रैंप की सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी। अब इसी कड़ी में विधायक किरण देव के योगदान में श्रद्धालुओं के लिए बस्तर गोंचा गुड़ी की एक और उपलब्धि जुड़ जाएगा।

बेटे को बचाना चाहते हो तो रुपये भेजो, अज्ञात नंबर से आई कॉल

दुष्कर्म के मामले की रची साजिश, ठगे लाखों रुपये

गौरेला पेंड्रा मरवाही। मरवाही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ माली को एक अज्ञात नंबर से फोन आया। कॉल करने वाले ने बताया, तुम्हारा बेटा दुष्कर्म के केस में फंस गया। इस मामले से बचाने के लिए दो लाख रुपये चाहिए।% माली ने उसे किस्तों में दो लाख रुपये दिए। जब उसे यह पता चला की उसके साथ ठगी की गई है तो मामले की शिकायत पुलिस से की। पीड़ित माली की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी अज्ञात मोबाइल धारक और अज्ञात खाताधारक के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, कुम्हारी गाव के पंडरीपानी में रहने वाले अवधेश कुमार भट्ट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरवाही में माली के पद पर पदस्थ हैं। तीन दिन पहले एक अज्ञात मोबाइल नंबर से अवधेश के मोबाइल पर कॉल आया। कॉल करने वाले ने कहा, तुम्हारा तुम्हारा लड़का रायपुर में पढ़ता है, जिसका नाम सुयश है। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दुष्कर्म किया है। उसे हमने थाने में बैठा रखा है। वह छूट सकता है..जितनी जल्दी हो सके उसे छुड़ा लो और आपको रायपुर आने की भी जरूरत नहीं है।

कॉल करने वाले ने आगे कहा कि जो फोन नंबर दे रहा हूं, उसमें एक लाख रुपये डाल दो। उसके कहने पर अवधेश कुमार भट्ट ने 80 हजार रुपये मोबाइल नंबर 95168199O5 पर ऑनलाइन माध्यम से भेजे और उसका स्क्रीनशॉर्ट लेकर भी भेजा। इसके बाद उसने कहा कि दूसरे फोन पे का नंबर दे रहा हूं, उसमें बाकी रुपये डालो। उसके कहने 9303260974 नंबर पर अवधेश ने 20 हजार रुपये और भेज दिए। इसके बाद कॉल करने वाले ने कहा कि यह रुपये तो पकड़ने वाले का मुह बंद कराने के लिए थे। थाना प्रभारी साहब के लिए अलग से एक लाख देना पड़ेगा बोला तो अवधेश ने कहा कि मैं छोटा कर्मचारी हूं इतना पैसा नहीं है।

इसके बाद कॉल करने वाले ने कहा कि जब तक पूरा पैसा नहीं डालोगे तब तक तुम्हारा लड़का नहीं

छूटेगा और उसके बाद वह अवधेश को चिल्लाने लगा। इसके बाद डरकर अवधेश ने कहा कि फोन की लिमिट खत्म हो गई है। रुपये नहीं जा रहे हैं तो अज्ञात व्यक्ति ने कहा कि मैं खाता नंबर दे रहा हूं उसे नोट करो और बैंक जाकर रुपये डालो खाता नंबर रिंकू देवी के नाम पर था, जिसके बाद अवधेश डरे सहमे खाता नंबर 38846174214 में बैंक जाकर पहले 70 हजार और उसके बाद 30 हजार रुपये डाल दिए। जमा पर्ची की रसीद की फोटो उसे भेजी।

इसके बाद कॉल करने वाले ने कहा कि डाक्टर साहब को जांच से नाम हटाने के लिए एक लाख नब्बे हजार रुपये अलग से देने पडेंगे। इसके बाद अवधेश को शंका हुई की उसके साथ फ्रॉड हुआ है। जिस नंबर से फोन आया था वह मोबाइल नंबर अवधेश के फोन से हट गया। ठगी का अहसास होने पर पीड़ित अवधेश कुमार भट्ट ने मरवाही थाने पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने तत्काल पीड़ित की शिकायत पर मोबाइल नंबर 9516819905 व 9303260974 व बैंक खाता क्रमांक 38846174214 धारक के खिलाफ धारा 318(4) ब्नहस् का अपराध दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है।

वहीं, पुलिस का कहना है मामले की शिकायत के बाद तत्काल पुलिस साइबर सेल की मदद से पीड़ित के एक लाख रुपये का ट्रांजेक्शन जो प्रोसेस में थे, उसे होल्ड कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है।

जंगल में रहने वालों ने खूब किया यूपीआई पेमेंट

सरगुजा। डिजिटल इंडिया की दौड़ में सबसे बड़ी चुनौती पेमेंट सिस्टम की थी, लोगों का भरोसा और सुरक्षित ट्रांजक्शन होना एक बड़ा काम था, खासकर सरगुजा जैसे वनांचल में लोगों का भीम और यूपीआई जैसे पेमेंट सिस्टम पर भरोसा करना थोड़ा कठिन था, लेकिन अब लोग बेखौफ होकर ऑनलाइन लेनदेन कर रहे हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बाजार में सरगुजा जिले में एक साल में तीन गुना बढ़ोतरी हुई है।

इस साल सरगुजा में भीम यूपीआई एप के जरिए 18 हजार 646 करोड़ का लेन देन किया गया। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के पोर्टल से इस आंकड़े की पुष्टि हुई है। तेजी से बढ़े ऑनलाइन लेन देन का मतलब है कि लोगों का झुकाव इंटरनेट बैंकिंग की ओर बढ़ा है। अब लोग छोटी छोटी जरूरतों के लिए ऑनलाइन भुगतान कर रहे हैं। शुरुआत में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के प्रति लोगों में भ्रम था। वो अपने पैसों की सुरक्षा को लेकर असुरक्षित महसूस करते थे। लेकिन अब सरगुजा के लोगों का जीवन पूरी तरह से ऑनलाइन लेनदेन पर निर्भर हो गया है। यहां भी अब लोग चाय के ठेले में 10 रुपये की चाय की पेमेंट से लेकर शॉपिंग मॉल में हजारों की खरीदी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से कर रहे हैं। यही वजह है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की संख्या के आंकड़ों में तेजी से इजाफा हुआ है।

घरौंदा सेंटर मामला : बिलासपुर हाईकोर्ट में शासन ने पेश किया जवाब

■ पांच अगस्त को होगी अगली सुनवाई

बिलासपुर। प्रदेश भर में चल रहे घरौंदा सेंटरों के मामले में शासन ने जवाब प्रस्तुत करते हुए कहा कि हमने रहने वालों की सुविधा के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है। कोर्ट ने पांच अगस्त को अगली सुनवाई निर्धारित कर दी है।

घरौंदा सेंटरों के मामले में जनहित याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। कोपलवाणी एनजीओ ने एक जनहित याचिका प्रस्तुत की है। रायपुर के एक संस्थान में भूख से बच्चों की मौत होने के बाद यह मामला सामने आया था। इसके बाद प्रदेश भर में संचालित हो रहे घरौंदा सेंटरों को लेकर भी इस याचिका में सुनवाई की गई।

पहले हुई सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कोर्ट कमिश्नरों से कहा था कि वे जाकर बिलासपुर समेत अन्य जगहों के सेंटरों में देखें कि बच्चों की स्थिति क्या है। जाकर पता करें उन्हें समय

पर भोजन दिया जा रहा है या नहीं। कोर्ट कमिश्नरों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर बिलासपुर के घरौंदा सेंटरों में जगह की कमी और खाने-पीने में परेशानी की बात कही थी। बुधवार को चीफ जस्टिस की डीबी में शासन ने जवाब में बताया कि हमारी ओर से सबकी जांच प्रक्रिया चल रही है। संबंधित अधिकारियों और विभाग को जरूरी सुविधाओं के लिये आवश्यक कदम उठाने निर्देशित किया गया है।

सांसद व विधायक ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किया पौधरोपण

■ ग्राम खैरा में जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम

महासमुंद। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया था। देश के नागरिकों से इस वर्ष वर्षा ऋतु में अपनी मां के सम्मान के लिए सम्मान स्वरूप एक पौधा लगाने का आह्वान किया है। जिसके तहत सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी एवं विधायक महासमुंद श्री योगेश्वर राजू सिन्हा ने आज एक पेड़ मां के नाम अभियान में ग्राम खैरा के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में आयोजित वन महोत्सव में विभिन्न फलदार पौधा रोपण किया गया और आम जनों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम का शुभारम्भ छत्तीसगढ़ महतारी की छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया गया।

इस अवसर पर सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी ने कहा कि आज हम प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के आह्वान पर यहां एक जगह एकत्र हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत ही भावनात्मक अपील की है। पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है। पेड़ जरूर लगाना चाहिए लेकिन सुरक्षा भी करना चाहिए। पेड़ लगाकर भूले नहीं, पेड़ को पानी दे और उसका रखरखाव करें। उन्होंने कहा कि यहां के बच्चे और ग्रामीण अपने घर या खेतों में अवश्य पेड़ लगाएं और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। पेड़ लगाने के नाम से महासमुंद जिला का अलग से पहचान बनाएं। इस अवसर पर उन्हांने अपनी माता श्रीमती हीरावती पटेल के नाम पर बरगद वृक्ष का रोपण किया।

वन महोत्सव कार्यक्रम में विधायक महासमुंद श्री योगेश्वर राजू सिन्हा ने कहा कि मां शब्द से सुनकर एक अलग भावना मन में जागृत हो जाता है। हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री के अपील पर अवश्य पेड़ लगाएं। यह पेड़ जब तक रहेगा तब तक मां का नाम रहेगा। आने वाले समय में यही पेड़ पर्यावरण के लिए मिल का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि पेड़ लगाने के साथ जाली लगाकर पेड़ की सुरक्षा करें। उन्होंने अपनी मां श्रीमती चुमकेश्वरी सिन्हा के नाम पर बेल पेड़ का पौध रोपण किया। उन्होंने कहा कि यहां स्कूल की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल भी बनाया जाएगा।

वनमंडलाधिकारी श्री पंकज राजपूत ने बताया कि पेड़ की असली महत्ता को कोरोना काल ने सिखाया है। आज हर व्यक्ति को अच्छी सेहत के लिए 20 पेड़ की आवश्यकता है। इसलिए हमें कम से कम 20 पेड़ लगाना ही चाहिए और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विकासखण्ड में निःशुल्क वाहन के माध्यम से ही फलदार और छायादार पेड़ों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। सभी ग्रामीण इसका अवश्य लाभ उठाएं। कलेक्टर श्री प्रभात मलिक, वनमंडलाधिकारी श्री पंकज राजपूत सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों ने भी एक पेड़ मां के नाम पर पौधरोपण कर जिलेवासियों से पर्यावरण संरक्षण में अपनी जिम्मेदारी निभाने का आग्रह किया।

महोत्सव में लोगों को निःशुल्क पौध का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष श्री यतेंद्र साहू, पार्षद श्रीमती मीना वर्मा, श्री महेंद्र जैन, श्री मुन्ना देवार, श्री मंगेश टकसाले, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्री पवन पटेल, सरपंच खैरा श्रीमती नीलम कोसरे, श्री चंद्रहास चंद्राकर, श्री संदीप दीवान, श्रीमती सुधा साहू, श्री मनीष शर्मा, श्री प्रकाश शर्मा, श्री प्रदीप चंद्राकर, श्री रमेश साहू, श्री देवेंद्र चंद्राकर, श्री हनीश बग्गा, श्री श्याम साकरकर उपस्थित थे तथा उप वनमंडलाधिकारी श्री अब्दुल वहीद खान एवं परिक्षेत्र अधिकारी श्री करमाकर एवं वन विभाग के कर्मचारी मौजूद थे।

श्री रामलला दर्शन योजना के तहत आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना

बिलासपुर। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत संभाग से 850 श्रद्धालुओं का जत्था अयोध्या धाम के लिए रवाना हुआ। इस यात्रा में जाने वाले श्रद्धालु अयोध्या के साथ काशी विश्वनाथ का भी दर्शन करेंगे। श्रद्धालुओं का स्टेशन पर भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान पूरा बिलासपुर जंक्शन राम के जयकारों से गूंज उठा।श्री रामलला दर्शन योजना के प्रति लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखा।

वहीं दर्शन के लिए जा रहे सभी श्रद्धालुओं का स्टेशन में तिलक लगाकर और माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान पारंपरिक लोक नृत्य और बाजे-गाजों के साथ श्रद्धालुओं को ट्रेन से रवाना किया गया। बिलासपुर की सीपत चौक सरकण्डा निवासी सीमा अग्रवाल ने कहा कि हम सौभाग्यशाली है कि हमें यह अवसर प्राप्त हुआ। हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 को

महासमुंद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के सचिव श्री दामोदर प्रसाद चन्द्रा के द्वारा जानकारी दी गयी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार 13 जुलाई 2024 दिन शनिवार को सम्पूर्ण देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है। जिस हेतु जिला न्यायालय महासमुंद के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के द्वारा नेशनल लोक अदालत के लिए खण्डपीठों का गठन कर विभिन्न प्रकरणों तथा प्री.लिटिगेशन का निराकरण किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य अपराधिक प्रकरणों धारा. 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, विद्युत संबंधी मामलों तथा पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया जाता हैं।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने रोग के संबंध में दी जानकारी

बलरामपुर। कलेक्टर श्री रिमिजियुस एक्का के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में मानसून काल में मौसमी बीमारियों से बचाव हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बसंत सिंह ने बताया है कि जल जनित रोग बरसात के मौसम में होता है। उन्होंने बताया कि एक ही समय में एक स्थान पर अनेक लोग एक ही प्रकार की बीमारी से प्रभावित होते हैं, तब ऐसी स्थिति को एपिडेमिक कहते हैं। जहां पर लोग हैजा, डायरिया, उल्टी-दस्त, टाइफाइड इत्यादि बीमारियों से ग्रसित होते हैं। ऐसे बीमारियां मुख्यतः दूषित पानी या दूषित भोजन को कारण होता है। इस प्रकार के बीमारियों से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जल जनित रोग से बचाव के संबंध में भी जानकारी दी है, कि पानी के स्त्रोत को हमेशा साफ रखें। बरसात के मौसम में उबला हुआ पानी पीयें, खाने के समान को हमेशा साफ रखें, दूषित भोजन का सेवन न करें।

बी.एस.सी. नर्सिंग प्रवेश परीक्षा का आयोजन 14 जुलाई को

महासमुंद। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर द्वारा आयोजित की जाने वाली बी.एस.सी. नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2024 का आयोजन रविवार 14 जुलाई 2024 को जिला मुख्यालय में निर्धारित 5 परीक्षा केन्द्रां में पूर्वाह्न 10ः00 से दोपहर 12ः15 बजे तक किया जाएगा। इस परीक्षा में जिले के 1473 परीक्षार्थी शामिल होंगे। कलेक्टर श्री प्रभात मलिक ने परीक्षा के सुचारू, निर्विघ्न रूप से संचालन के लिए डिप्टी कलेक्टर श्री मनोज कुमार खाण्डे को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इसी प्रकार प्रवेश पत्र तथा उत्तरशीट में दिए गए फोटो एवं हस्ताक्षर के सूक्ष्म मिलान के लिए 03 सदस्यीय उड़नदस्ता का गठन किया गया है। जिमसें श्री मोहित कुमार अमिला, नायब तहसीलदार, श्री प्रमोद कन्नौजे व्याख्यात स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल नयापारा एवं श्री डी.एन. जांगड़े सहायक कार्यक्रम समन्वयक, शिक्षा विभाग को उड़नदस्ता नियुक्त किए गए हैं। इसी तरह परीक्षा केन्द्रां तक गोपनीय सामग्री पहुंचाने हेतु परिवहन अधिकारी/पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

बारिश के साथ शुरू हुआ बीमारियों का कहर

सुकमा। बारिश की शुरुआत के साथ ही बीमारियों ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। इन बीमारियों के बीच सुकमा जिले में डेंगू से पहली मौत का मामला सामने आया है। बीते दिनों एक आरक्षक की पत्नी डेंगू प्रभावित होने के बाद सुकमा जिला अस्पताल में भर्ती कराई गई थी। देर रात महिला को एबी+ खून की भी आवश्यकता पड़ी थी। सुकमा एसपी किरण चव्हाण ने तुरंत खून की व्यवस्था भी करवाई थी। लेकिन महिला की स्थिति बिगड़ती चली गई। इसके बाद उसे जगदलपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद प्रशासन डेंगू और मलेरिया से निपटने के लिए आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, नगरीय क्षेत्रों में लोग छिड़काव और फॉगिंग की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि बस्तर भर में मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत मलेरिया से बचाव के लिए टीकाकरण भी किया गया। वहीं, बारिश के मौसम में खास तौर पर जुलाई से जनवरी के बीच डेंगू, मलेरिया के मामले बढ़ते नजर आते हैं।

शादी के दौरान चोरों ने पचास हजार और जेवरात किए पार

कोरबा। मानिकपुर चौकी क्षेत्र के शारदा विहार क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान चोरी की घटना सामने आई है। अज्ञात चोरों ने रात के वक्त नशीली दवा का छिड़काव कर 50 हजार रुपये नकद सहित सोने-चांदी के जेवरातों की चोरी कर ली। चोरी के दौरान दुल्हन की नजर पड़ी, तब चोरों ने दुल्हन के साथ मारपीट की और फरार हो गए। मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरु कर दी है। जानकारी के अनुसार, शारदा विहार सामुदायिक भवन में सीतामणी निवासी रवि यादव की बहन पूजा यादव का विवाह समारोह नौ जुलाई से चल रहा है। 10 जुलाई को को हल्दी कार्यक्रम था। हल्दी कार्यक्रम होने के बाद भवन के अंदर और बाहर पंडाल पर परिजन और घरवाले सो गए। एक कमरे में सभी मेहमानों के बैग रखे हुए थे। देर रात कुछ युवक आए और चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। पूजा यादव ने बताया कि रात लगभग 2:00 बजे पूरा परिवार सो रहा था। इस दौरान उसे आवाज आई और देखा तो एक युवक चेहरा छुपाते हुए भाग रहा था।

बच्चा चोरी कर भाग रहा था युवक, लोगों ने पकड़कर कर दी पिटाई, किया पुलिस के हवाले

कोरबा। बुधवारी थाना क्षेत्र में एक मासूम बच्चे की चोरी करने के प्रयास में लोगों ने एक युवक की पिटाई कर दी। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। तीन साल का बच्चा समद अंसारी बुधवारी स्थित गणेश पंडाल के पास मैदान में अपने बड़े भाई के साथ खेल रहा था। इस दौरान अचानक युवक घूमते हुए आया और तीन साल के मासूम गोदी में उठाकर ले जा रहा था। बड़ा भाई दौड़ते हुए घर गया और इसकी सूचना परिजनों को दी। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया और सभी ने मासूम बच्चे की तलाश शुरू कर दी।

बुधवारी मुख्य मार्ग बाजार के पास बच्चों को लेकर युवक जा रहा था। इस दौरान परिजनों की नजर पड़ी और दूर से ही चोर-चोर चिल्लाने लगे। युवक बच्चे को छोड़कर भाग रहा था। राहगीरों ने उसे पकड़ लिया और सभी ने मिलकर उसकी धुनाई कर दी। इसके बाद उसे सीएसईबी चौकी पुलिस के हवाले कर दिया। बच्चे के पिता नसीम अंसारी ने

बताया कि बच्चों को लेकर मैदान में खेलाने के लिए गया हुआ था। काम पड़ने पर घर चला गया। इस दौरान यह घटना सामने आई। समय रहते अगर युवक को नहीं पकड़ा जाता तो बच्चों के साथ कोई भी अनहोनी हो सकती थी।

सीएसईबी चौकी पुलिस का कहना है कि नशे में धुत एक 26 वर्षीय युवक मौके पर पहुंचा और उसे अपना बच्चा कहकर गोद में उठाकर भागने लगा। उससे आगे पूछताछ की जा रही है।

शौच के लिए गए शख्स पर भालू ने किया हमला

■ डेढ़ घंटे तड़पता रहा बाबूलाल, अस्पताल में डॉक्टर ने नहीं किया इलाज

गौरेला पेंड्रा मरवाही। मरवाही में भालू के हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई। ग्रामीण देर रात घर से कुछ ही दूरी पर शौच के लिए गया हुआ था, तभी भालू ने उस पर हमला कर दिया। घायल ग्रामीण को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरवाही लाया गया था, जहां अस्पताल प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगा है। डॉक्टर की देरी की वजह से 108 एंबुलेंस स्टाफ और वार्ड बॉय अस्पताल में घायल का इलाज करते रहे। आरोप है कि महज 10 कदम दूर से डॉक्टर टेलीफोन से इलाज करवाते रहे। जनप्रतिनिधियों सहित परिजनों ने वन विभाग और अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है।

जानकारी के अनुसार, मरवाही वन परिक्षेत्र अंतर्गत लिटयासरई गांव में लटकोनीखुर्द का रहने वाला बाबूलाल रिश्तेदारी में आया हुआ था। देर रात शौच के लिए जब बाबूलाल घर के पास स्थित तालाब की ओर गया, तभी

वहां पहले से मौजूद भालू ने ग्रामीण को देखकर उस पर हमला कर दिया। बाबूलाल ने किसी तरह खुद को भालू के चंगुल से बचकर घर तक पहुंचा। इसके बाद उसे 108 संजीवनी एक्सप्रेस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरवाही लाया गया।

हालांकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर को मौजूद रहना था, लेकिन जब काफी देर तक डॉक्टर नहीं पहुंचा तो संजीवनी एक्सप्रेस के मेडिकल स्टाफ ने वार्ड बॉय के साथ मिलकर घायल ग्रामीण की चिकित्सा शुरू कर दी। उसे टांके लगाने के साथ-साथ अन्य उपचार दिया गया। डॉक्टरों की अनुपस्थिति की सूचना जिला पंचायत सदस्य को भी दी गई। लगभग 1:30 बजे रात तक डॉक्टर घायल की चिकित्सा में उपस्थित नहीं हो सका और लगभग 3:00 बजे घायल की मृत्यु हो गई।

मामले पर परिजनों और जिला पंचायत सदस्य ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि लगभग डेढ़ घंटे गंभीर मामला आने के बाद डॉक्टरों का उपस्थित न होना अस्पताल प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है। यदि डॉक्टर मौजूद होते तो कम से कम उसे जिला अस्पताल ही रेफर कर देते। वहीं, स्थानीय वन अमला भी नहीं पहुंचा। मामले पर विकासखंड चिकित्सा अधिकारी का बयान पोल खोलने वाला है।

वार्ड से डॉक्टर्स रूम की दूरी महज 10 कदम है, लेकिन वार्ड बॉय और संजीवनी एक्सप्रेस का स्टाफ घायल का उपचार करता रहा। गंभीर रूप से घायल के पहुंचने के बाद भी चिकित्सा उन्हें फोन पर इंस्ट्रक्शन देता रहा। परिजनों का आरोप मौके के विजुअल और मौके पर मौजूद जनप्रतिनिधियों का आरोप भी इस बात की ओर ही इशारा कर रहा है कि डॉक्टर ने शुरुआती इलाज में लापरवाही की, जिसकी वजह से ग्रामीण की मौत हो गई।

संक्षिप्त समाचार

सड़क हादसे में घायल हुए भाजपा नेता प्रबल प्रताप सिंह, अस्पताल में भर्ती

रायपुर। छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता प्रबल प्रताप सिंह सड़क हादसे में घायल हो गए हैं। उनकी कार को एकट्रक ने ठोकर मार दी है, जिसके चलते वे घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए रायपुर लाया गया है। अस्पताल में इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक, प्रबल प्रताप सिंह बिलासपुर से रायपुर जा रहे थे। इसी बीच सरगांव क्षेत्र के पास अचानक से ट्रक ने कार में टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कार में सवार छत्तीसगढ़ बीजेपी के मंत्री रहे दिवंगत नेता दिलीप सिंह जूदेव के बेटे प्रबल प्रताप सिंह घायल हो गए।

वंदिता, मानसी व सुमीत चार्टर्ड एकाउंटेंट इंस्टीट्यूट के परीक्षा में सफल

रायपुर। चार्टर्ड एकाउंटेंट इंस्टीट्यूट के नतीजे गुरुवार को घोषित किए गए हैं। इसमें बूढ़ापारा निवासी कुमारी वंदिता व्यास , गुढियारी निवासी कुमारी मानसी शर्मा व लाखेनगर निवासी सुमीत मिश्रा ने सफलता अर्जित की है। नतीजे आने के बाद परिजनों में खुशी का माहौल है।

आप भी जुड़े एक पेड़ माँ के नाम अभियान से

रायपुर। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अपील पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की गई है। आप सभी इस अभियान का हिस्सा बनें। अपने घर-आँगन, खेत में अपनी माता जी के साथ या माता जी की स्मृति में पौधा लगाते हुए अपनी तस्वीर लें। इस तस्वीर पर एक पेड़ माँ के नाम प्रोफाइल पिक्चर फ्रेम लगाकर सोशल मीडिया पर डिस्प्ले के रूप में लगाएं।दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर इस अभियान से जुड़ें।

सूरी नए मुख्य आयकर आयुक्त होंगे एक्का का तबादला ओडिशा

रायपुर। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर विभाग के 9 अफसरों को नई जिम्मेदारी दी है। प्रणीत महल सूरी रायपुर एमपी-सीजी के नए मुख्य आयकर आयुक्त होंगे। वे एडिशनल चार्ज के रूप में यह जिम्मेदारी निभाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्य आयकर आयुक्त वीर बिरसा का तबादला ओडीसा हो गया है।

भीम सिंह कंवर सीएसपीडीसीएल में संचालक एवं प्रबंध संचालक पदस्थ

रायपुर। राज्य शासन के ऊर्जा विभाग द्वारा आज जारी आदेश के तहत छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के कार्यपालक निदेशक (संचालन/संधारण), श्री भीम सिंह कंवर को छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में संचालक एवं प्रबंध संचालक के पद पर पदस्थ किया गया है।

जमीन के लिए जहर बन रहे प्रतिबंधित पॉलीथिन पर सख्त हुआ निगम

धमतरी। जिले में प्रतिबंधित पॉलीथिन और डिस्पोजल सामान पर गुरुवार को नगर निगम की टीम ने कार्रवाई की है। निगम ने शहर के अलग-अलग दुकानों में दबिश देकर पॉलीथिन डिस्पोजल सामान जब्त किया है। इस कार्रवाई से दुकानदारों के बीच हड़कंप मच गया है। इस बारे में नगर निगम उप आयुक्त ने जानकारी दी कि शहर के 17 दुकानों से करीब 15 पेटी प्रतिबंधित पॉलीथिन और डिस्पोजल जब्त की गई है। लगातार समझाईश के बावजूद व्यापारी पॉलीथिन और डिस्पोजल का उपयोग करना नहीं छोड़ रहे हैं। नगर निगम की ओर से 17 दुकान जिसमें खोमचे समेत शहर के छोटे बड़े दुकानों से 15 हजार का जुर्माना भी वसूला गया है।बार-बार समझाईश के बाद भी कुछ दुकानदार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार ने पॉलीथिन पहले से ही बैन कर रखा है। बावजूद इसके पॉलीथिन का उपयोग किया जा रहा है। शहर में लगातार प्रतिबंधित पॉलिथीन पर कार्रवाई के बाद भी इसकी बिक्री रुकी नहीं है।

शराब घोटाला मामला, ईडी एसीबी की नई एफआईआर को निरस्त करने की मांग

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले मामले में ईडी और एसीबी की एफआईआर को निरस्त करने की मांग की गई है। इसके लिए अनिल टूटेजा,अनवर ढेबर समेत दूसरे आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट में इसे लेकर क्रिमिनल मिस्लेनियस पिटीशन पर सुनवाई चली। मामले में लंबी बहस के बाद चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। शराब घोटाले को लेकर एसीबी और ईडी ने अनिल टुटेजा , यश टुटेजा , अनवर ढेबर , विधु गुप्ता , निरंजन दास और एपी त्रिपाठी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये सभी पहले से ही रायपुर सेन्ट्रल जेल मे निरुद्ध हैं। अपने खिलाफ किए गए नए एफआईआर को निरस्त करने की मांग लेकर सभी आरोपियों ने हाईकोर्ट का रुख किया। मामले में बुधवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र अग्रवाल की डीबी में सुबह से बहस शुरू हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कहा, कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने जब एफआईआर क्वेश कर दी थी, तब पुराने तथ्यों और आधारों पर ही फिर एफआईआर दर्ज करना वैधानिक नहीं है। मामले में नए सिरे से जांच किए जाने के बाद ही यह कार्रवाई हो सकती थी। मामले में सभी पक्षों के तर्कों और बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट की डीबी ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है।

संसदीय व्यवस्था में वित्तीय समितियों की भूमिका अहम : डॉ. रमन

■ विधान सभा की वर्ष 2024-25 के लिए गठित लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति की संयुक्त बैठक

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधान सभा की वर्ष 2024-25 के लिए गठित वित्तीय समितियों लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति की संयुक्त बैठक आज विधान सभा परिसर स्थित समिति कक्ष कमांक-1 में संपन्न हुई। संयुक्त समितियों की गुरुवार को संपन्न प्रथम बैठक में मान. विधान सभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे। बैठक में लोक लेखा समिति के सभापति डॉ. चरणदास महंत, प्राक्कलन समिति के सभापति अजय चन्द्राकर, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सभापति अमर अग्रवाल, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के सभापति धरम लाल कौशिक एवं समितियों के सदस्यगण, विधान सभा के सचिव दिनेश शर्मा, प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़, यशवंत कुमार, वित्त विभाग की सचिव शारदा वर्मा एवं संचालक, राज्य संपरीक्षा, पुष्पा साहू उपस्थित थे।

समिति की प्रथम बैठक को सम्बोधित करते हुए विधान सभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि इस वर्ष वित्तीय समितियों में दो पूर्व विधान सभा अध्यक्ष एवं शेष दो समितियों में से अतिवरिष्ठ मान. सदस्य सभापति के रूप में नामित हैं। इन वरिष्ठ सदस्यों के अनुभवों एवं संसदीय ज्ञान का लाभ हम सब को मिलेगा। संसदीय शासन प्रणाली में समितियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसद एवं विधान मंडल के बहुत से कार्य लघु सदन के रूप में समितियों के माध्यम से किये जाते हैं। विधान सभा में 21 समितियां है, इनमें लोक लेखा समिति एवं प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति एवं स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति सदन की वित्तीय समितियां हैं। वित्तीय कामकाज की संपूर्ण समीक्षा, नियंत्रण एवं यथा आवश्यक सुझाव, अनुशंसा संबंधी कार्य इन समितियों के द्वारा किया जाता है। लोकलेखा समिति विधान सभा की महत्वपूर्ण वित्तीय समिति है। इस समिति का महत्वपूर्ण कार्य शासन पर वित्तीय

नियंत्रण रखना होता है। लोकलेखा समिति का मुख्य कार्य यह देखना होता है कि विधान सभा द्वारा जो बजट पारित किया गया है, उसका खर्च उन्हीं योजनाओं एवं कार्यो में सही तरीके से किया गया है या नहीं। समिति यह भी देखती है कि निरर्थक व्यय या वित्तीय अनियमितता तो नहीं की गई है। संविधान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है, जो संघ-राज्य क्षेत्र में शासन द्वारा किये जाने वाले व्यय में होने वाली खामियों के संबंध में अपना प्रतिवेदन सभा पटल पर प्रस्तुत करते हैं। प्राक्कलन समिति विभागों के प्राक्कलनों पर विचार करती है और विभागीय नीति के अनुरूप खर्च पर नियंत्रण करने तथा बचत के सुझाव देती है। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति विधान सभा की महत्वपूर्ण वित्तीय समिति है। सरकारी उपक्रमों सबंधी समिति के माध्यम से विधायिका राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यकलापों पर निगरानी रखती है। स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति छत्तीसगढ़ विधान सभा की चतुर्थ वित्तीय समिति है। स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा जो कार्य संपादित किये जाते है।

इस अवसर पर लोक लेखा समिति के सभापति डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि संसदीय समिति में वित्तीय समितियों की अहम भूमिका होती है। समितियॉ सभा का लघु स्वरूप होती हैं एवं यह समितियॉ अपने कार्यो के माध्यम से ससदीय प्रजातंत्र के मूल तत्व कार्यपालिका की विधायिका के प्रति जबाबदेही को सुनिश्चित करेगी।

प्राक्कलन समिति के अजय चन्द्राकर ने कहा कि, विभागों की कार्य पद्धतियों का परीक्षण कर विभागों की कार्य प्रणाली में किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है। इस विषय पर समिति अपना ध्यान केन्द्रित करेगी।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सभापति अमर अग्रवाल ने कहा कि, यह समिति प्रमुखत: सरकारी उपक्रमों के लेखे एवं प्रतिवेदनों, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक तथा सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता और कुशलता की जॉच करती है।

स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के सभापति धरमलाल कौशिक ने कहा कि प्रदेश के स्थानीय निकाय एवं पंचायतों के वित्तीय कामकाज की संपूर्ण समीक्षा, नियंत्रण एवं यथा आवश्यक सुझाव, अनुशंसा संबंधी कार्य इस समिति के द्वारा किया जाता है।

इस अवसर पर सभी वित्तीय समितियों के सभापतियों ने विधान सभा अध्यक्ष को डॉ. रमन सिंह को आश्वस्त किया कि समितियों की अधिक से अधिक बैठकें कर कंडिकाओं का शीघ्र निराकरण कर सदन में अधिक से अधिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जायेंगे। इस अवसर पर विधायक धर्मजीत सिंह, कुंवर सिंह निषाद, अनुज शर्मा, नीलकंठ नेताम, प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़, यशवंत कुमार एवं सचिव, वित्त विभाग, शारदा वर्मा एवं संचालक, राज्य संपरीक्षा पुष्पा साहू ने भी अपने विचार व्यक्त किये। अंत में राजेश मूणत ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया।

पीएम श्री योजना : छत्तीसगढ़ के 52 स्कूल दो-दो करोड़ की लागत से सवरेंगे

रायपुर। भारत सरकार की ओर से पीएम श्री योजना के अंतर्गत तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ के 52 शालाएं स्वीकृत की गई है। इस योजना के तहत पहलीं से 12वीं तक की 47 शालाएं और कक्षा 6वीं से 12वीं तक की पांच स्कूल शामिल हैं। पीएम श्री योजना अंतर्गत आने वाले स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, विज्ञान और गणित के लिए अत्याधुनिक लैब्स, खेल सुविधाएं और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं विकसित की जाएगी।

इससे पहले राज्य में प्रथम चरण में 211 शालाओं को पीएम श्री योजना की स्वीकृति मिली चुकी है। इस तरह राज्य में कुल 263 शालाओं को पीएम श्री योजना के अंतर्गत मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किए जाने की स्वीकृति मिल चुकी है। प्रथम चरण में पीएम श्री योजना के तहत स्वीकृत शालाओं को अपग्रेड किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

राज्य में पीएम श्री योजना का शुभारंभ 19 फरवरी 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने किया था। उन्होंने इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर किए जा रहे प्रयासों को सराहा था। पीएम श्री के तहत प्रति स्कूल 2-2 करोड़ रूपए व्यय कर आदर्श स्कूल के रूप में विकसित करने की योजना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पीएम श्री योजना के अंतर्गत शालाओं को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। पीएम श्री योजना के तहत चयनित शालाओं का अकादमिक एवं अधोसंरचनात्मक सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इन शालाओं में वर्चुअल रियलिटी लैब, अटल टिकरिंग, एआई रोबोटिक्स, गेमीफाइड लर्निंग के माध्यम से शिक्षा की सुविधा उपलब्ध रहेगी, इसके अलावा इन शालाओं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, इंडोर एवं आऊटडोर स्पोर्ट्स एवं गेम्स की सुविधाओं के साथ-साथ समर कैंप, एडवेंचर स्पोर्ट, कैरियर गाइडेंस एवं काउंसलिंग का लाभ मिलेगा।

छत्तीसगढ़ के सरकारी शिक्षकों की बढ़ी टेंशन

अब छुट्टी लेने के लिए करना होगा ऑनलाइन अप्लाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी शिक्षकों की मनमानी छुट्टी लेने की प्रथा को रोकने के लिए विष्णुदेव साय सरकार ने नया निमय लागू किया है। दरअसल, शिक्षक मनचाहे दिन छुट्टियों में रहते हैं या फिर स्कूलों में बच्चों की मौजूदगी में भी आराम फरमाते रहते हैं। इस पर साय सरकार सख्ती दिखाते हुए शिक्षकों के छुट्टी लेने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब 15 जुलाई से शिक्षकों को छुट्टी लेने के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। शासकीय स्कूलों की शिक्षक अब विभागीय पोर्टल के माध्यम से छुट्टी के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके प्रक्रिया के लिए शिक्षा विभाग योजना बनाने के लिए तैयारी कर

रही है। ऑनलाइन छुट्टी के लिए कई प्रक्रियाएं हैं। सरकारी शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की छुट्टियां भी मिलती हैं। अब छुट्टी के लिए शिक्षक आकस्मिक छुट्टी, अर्जित छुट्टी आदि के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन जमा करने के तुरंत बाद छुट्टी मिलना संभव नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद, संबंधित अधिकारी स्वीकृति प्रदान करेगी, तब जाकर शिक्षकों को छुट्टी मिलेगी। अस्वीकृति दिए जाने पर छुट्टी के लिए आवेदन रद्द कर दिया जायेगा। शिक्षक पोर्टल पर अपने अवकाश आवेदन की स्थिति को भी ट्रैक कर सकेंगे। इसके अलावा इन्हें कई और भी सुविधाएं मिलेंगी।

इसे लेकर शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। शिक्षकों की छुट्टियों के लिए एक वेबसाइट लांच किया गया है। शिक्षा विभाग ने पूरी मामले की जानकारी देते हुए बताया कि छुट्टी की स्वीकृति की प्रोसेस को आसान करने के लिए अवकाश मैनेजमेंट पोर्टल बनाया किया जा रहा है। इसके लिए eduportal.cg.nic.in/education वेबसाइट को लांच किया गया है। इसकी जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर संभागीय स्तर के संचालकों को आदेश जारी किया गया है।

कानून व्यवस्था पर होगा सदन में संग्राम

विधानसभा घेरने की कांग्रेस ने बनाई रणनीति

रायपुर। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सरकार पर आक्रामक हमले की तैयारियों में जुट गई है। 22 जुलाई से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरु होने वाला है। सत्र से पहले ही कांग्रेस ने अपने तेवर कड़े करने शुरु कर दिए हैं। रायपुर में दीपक बैज ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि हम कानून व्यवस्था पर कोई भी समझौता नहीं करेंगे। प्रदेश में जिस तरह से अपराध के ग्राफ बढ़े हैं उससे जनता परेशान है। प्रदेश में ऐसा लग रहा है जैसे जंगल राज है।

जगदलपुर में हुए दोहरे हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि कानून व्यवस्था का राज कायम करने में ये सरकार विफल साबित हो रही है। दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ रहे हैं। आम लोग इस बढ़ते अपराध से परेशान हैं। सरकार अपराधियों पर लगाम लगाने में फेल साबित हो रही है। कांग्रेस ने विष्णु देव साय सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया।

पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है तब से छत्तीसगढ़ में क्राइम रेट बढ़ा है। बीते पांच दिनों के भीतर तीन बड़ी घटनाएं घटी हैं। पूरे प्रदेश में अपराध बढ़ रही है। ये सुशासन नहीं बल्कि जंगल राज है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। अपराधियों को संरक्षण देने का काम सरकार कर रही है। प्रदेश की जनता इससे आक्रोश में है। हम विधानसभा घेराव की तैयारी कर रहे हैं।

दीपक बैज ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस बीजेपी की सरकार से सवाल पूछना चाहती है। हमें ये बताया जाए कि ये सुशासन राज है या फिर प्रदेश में जंगल राज है। कहीं ये सरकार अपराध और अपराधियों को संरक्षण देने की कोशिश तो नहीं कर रही है। कानून व्यवस्था को लेकर हम जनता की आवाज उठाएंगे। विधानसभा सत्र के दौरान हम विधानसभा घेराव की तैयारी भी कर रहे हैं।

बीएनएस में अब कुल 358 नवीन धाराएं, 175 धाराएं बदल गईं

नवीन कानूनों के प्रवर्तन पर आयोजित कार्यशाला में दी गई जानकारी

कांकेर। पूरे देश में एक जुलाई 2024 से देश में तीन नए कानून लागू हो गए हैं, जिनमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 2023 शामिल हैं। स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1860 में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) लागू हुई थी, में केन्द्र सरकार ने 16 दशक बाद 2023 में व्यापक बदलाव किए हैं, जिसमें सिर्फ धाराएं ही नहीं बदलीं, बल्कि सजा और जुर्माने के प्रावधान में भारी परिवर्तन किए गए हैं। पुराने कानून की बहुचर्चित धाराएं 302 हत्या अब 103, ठगी या धोखाधड़ी 420 अब 318 (4), चोरी 379 अब 303(2) व दुष्कर्म 376 आईपीसी अब 64 बीएनएस कहलाएंगी। आने वाले समय में अब इंडियन पीनल कोड 1860 (आईपीसी) की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 (बीएनएस), क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (सीआरपीसी) 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (बीएनएसएस) और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो गई है। नवीन कानूनों के विभिन्न प्रावधानों से अवगत कराने एवं आमजनता को जागरूक करने के उद्देश्य से आज पुलिस

विभाग द्वारा कार्यशाला आयोजित कर कांकेर के वरिष्ठ नागरिकों एवं मीडिया प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई, साथ सामान्यत: प्रयुक्त होने वाली अलग-अलग धाराओं एवं उनमें निहित उपधाराओं के बारे में बताया गया।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित 'नवीन कानूनों का प्रवर्तन' विषय पर आयोजित कार्यशाला में प्रशिक्षु आईपीएस श्री संदीप कुमार पटेल (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भानुप्रतापपुर) ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की विभिन्न प्रमुख धाराओं व उप धाराओं के बारे में पीपीटी के माध्यम से बताया। इस अवसर पर डीएसपी श्री जी.एस. साव ने नए कानून के विभिन्न प्रावधानों पर जानकारी दी। साथ ही कानून के विशेषज्ञ अधिवक्ताओं ने भी नवीन कानून पर प्रकाश डाला।

124(क) राजद्रोह खत्म, अब होगी देशद्रोह के तहत कार्रवाई

कार्यशाला में बताया गया कि अंग्रेजों के समय के कानून 124(क) आईपीसी को नए कानून के तहत् खत्म कर उसकी जगह देशद्रोह कर दिया गया है। लोकतांत्रिक देश में सरकार की आलोचना कोई भी कर सकता है। मगर किसी ने सशस्त्र विरोध, बम धमाका करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

आईपीसी की 511 धारा अब बीएनएस में 358 धारा

इस माह (जुलाई-2024) से सरकार बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) लागू कर दी है। आईपीसी में 511 धाराएं थीं, जबकि बीएनएस में 358 धाराएं है। 175 धाराएं बदल गई हैं, 18 नई जोड़ी गई हैं, साथ ही 22 धाराएं खत्म हो गई है। इसी तरह सीआरपीसी में में 533 धाराएं है, इनमें 160 धाराए बदली गई हैं। नौ नई धारा जोड़कर नौ को खत्म कर दिया गया है। इसमें पूछताछ से ट्रायल तक सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करने का प्रावधान हो गया है।

प्रवेश एवं प्रतियोगी परीक्षाओं एवं मौसमी बीमारियों के संबंध में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन से महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर राज्य के सभी संभागायुक्त और कलेक्टर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक ली। उन्होंने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न संस्थानों में भर्ती परीक्षाओं सहित अन्य रोजगार परीक्षाओं में सुचिता और सुरक्षा को लेकर भारत सरकार द्वारा अभियान चलाया जा रहा है।

इसके लिए सभी जिलो के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षाओं को लेकर सर्तकता एवं संवेदनशीलता से कार्य करें। इस संबंध में मुख्य सचिव ने कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार परीक्षा केन्द्रों पर सतर्कता बरती जाए। इसी तरह से भारत सरकार द्वारा एक जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक स्टॉप डायरिया अभियान चलाया जा रहा है।

मुख्य सचिव ने डायरिया नियंत्रण के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।

मुख्य सचिव ने आगामी दिनों में आयोजित होने वाली नीट-पीजी, यूजीसी-नेट सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यंत सतर्कता बरतने के निर्देश दिए है। उन्होंने प्रत्येक जिले में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा है जिले के अंदर आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए बनाये जाने वाले परीक्षा केन्द्रों पर अत्यंत सुरक्षा और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं की जाए। इसी तरह से स्टॉप डायरिया अभियान के अंतर्गत ऐसे संवेदनशील क्षेत्र जहां पिछले वर्षों में डायरिया के प्रकरण हुए है वहां अत्यंत सतर्कता बरती जाए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि पांच वर्ष तक के सभी बच्चों को ओआरएस और जिंक की गोलियां घर-घर जाकर मितानिनों के माध्यम से वितरित की जाए।

जहां पर कहीं डायरिया के प्रकरण की जानकारी मिलती है तो वहां पर तुरंत मेडिकल टीम भेजकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए। डायरिया से पीड़ितों का समुचित इलाज कराया जाए। मुख्य सचिव ने पेयजल के स्त्रोतों की साफ-सफाई, पाइपों के लिकेज होने की शिकायत पर तत्काल पाइपों का सुधार एवं नए पाइप लगाए जाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।

बैठक में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, गृह एवं जेल विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, सभी संभागायुक्त एवं कलेक्टर सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

एक पेड़ मां के नाम किया गया पौधरोपण

नारायणपुर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के अवसर पर लॉन्च किए गए एक पेड़ मां के नाम योजना के अंतर्गत 11 जुलाई को नारायणपुर शहर के अंतर्गत केंद्रीय स्कूल नारायणपुर, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आदेश्वर स्कूल शांति नगर एवं शासकीय आत्मानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय नारायणपुर में कुल 2000 नग पौधारोपण वन विभाग द्वारा कराया गया। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर बिपिन माझी के उपस्थिति में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान में आर.एस. मंडावी, उपवन मंडल अधिकारी, अशोक सोनवानी आदि शामिल थे।

भारत-रूस मित्रता को जीवंतता देने का सार्थक प्रयास

ललित गर्ग

भारत-रूस की मैत्री को नये आयाम देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राष्ट्रपति पुतिन ने न केवल मैत्री के धागों एवं द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूती दी है, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को नये शिखर देने का प्रयास किया है। उनकी यह यात्रा दोनों देशों के लिये एक नए सोच के साथ नये सफर का आगाज है। एक ऐसे समय में, जबकि यूक्रेन-रूस युद्ध को पश्चिमी देशों के विरोध के कारण रूस दुनिया में अलग-थलग है, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में पहले विदेश यात्रा के लिये रूस का चयन करके जता दिया है कि भारत-रूस की मैत्री अक्षुण्ण है और किसी भी तरह के दुनिया के दबाव में यह दोस्ती कमजोर नहीं पड़ने वाली है। भारत ने जहां मैत्री को प्रगाढ़ बनाने की दिशा में उल्लेखनीय उपक्रम किये हैं, वहीं अपने मित्र देश को युद्ध के खिलाफ और शांति के पक्ष में अपना स्पष्ट रुख भी जताया है। मोदी की इस यात्रा की एक बड़ी निष्पत्ति यह है कि रूस में अब दो नये वाणिज्यिक दूतावास खुलने जा रहे हैं, जिससे हमारी आर्थिक गतिविधियां तेजी से एवं ज्यादा बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इस रूस यात्रा को लेकर पश्चिमी देशों ने विरोध जताया है। लेकिन प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि भारत के लिए रूस की मैत्री बहुत महत्वपूर्ण है। भारत अपने मैत्री-मूल्यों को किसी भी दबाव में कमतर नहीं होने देगा। भले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की इस यात्रा पर अपनी निराशा जाहिर करते हुए इसे शांति प्रयासों को झटका तक बता चुके हो या अमेरिका ने भी यात्रा को लेकर अपनी चिंता जता दी हो। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपनी युद्ध विरोधी सोच के चलते ही यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूस नहीं गए थे। दोनों देशों के बीच होने वाली सालाना द्विपक्षीय शिखर बैठक भी 2022 के बाद से नहीं हो पाई थी। इससे रूस के कुछ हलकों में यह धारणा बनने लगी थी कि भारत अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रभाव में रूस से दूरी बनाए रखना चाहता है। दुनिया में बन रही इस नई धारणा को तोड़ना जरूरी था, इसी दृष्टि से इस यात्रा के पीछे जहां द्विपक्षीय रिश्तों को संदेहों और अविश्वासों से मुक्त करने का ध्येय था, वहीं अंतरराष्ट्रीय हलकों में यह स्पष्ट संदेश भेजना था कि भारत को किसी तरह के दबाव के जरिए इस या उस पक्ष में झुकाना संभव नहीं है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत में इसका जिक्र किया कि उनके रूस आने पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। दुनिया भर में इस यात्रा को गहरी उत्सुकता से देखा जा रहा है। मौजूदा अंतरराष्ट्रीय हालात को ध्यान में रखें तो यह कोई अचरज वाली बात भी नहीं है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों का जोर इस बात पर रहा है कि भारत रूस से अपनी करीबी खत्म करे। भारत अब एक स्वतंत्र ताकत है, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थ-व्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, बड़े शक्तिशाली देशों के लिये भी भारत एक बाजार है। इसलिये भारत किसी भी दबाव में न आते हुए शुरू से ही यह स्पष्ट कर रखा है कि वह अपने राष्ट्रहित पर आधारित स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम रहेगा। रूस समर्थकों ने भले ही यह दर्शाना चाहा हो कि मोदी की यात्रा से भारत ने पश्चिम को चुनौती दी है और इससे पश्चिमी देश 'ईर्ष्या से जल रहे हैं', परंतु असल में भारत ऐसा कोई मंतव्य नहीं रखता है। यह यात्रा अनेक कारणों एवं दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण रही, यात्रा के दौरान दोनों देशों में सहयोग बढ़ाने के समझौते तो हुए ही, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मित्र राष्ट्र को मैत्रीपूर्ण सलाह देते हुए पूरी बेबाकी से कहा, 'युद्ध के मैदान से कोई हल नहीं निकलता।' यह प्रधानमंत्री मोदी का वैसा ही बयान है जैसा दो साल पहले समरकंद में पुतिन से बातचीत के दौरान उन्होंने दिया था कि 'यह युद्ध का दौर नहीं है'। असल में भारत हमेशा से शांति के उजालों एवं युद्ध के अंधेरों से मुक्ति का ही समर्थक रहा है। भारत की स्पष्ट मान्यता है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। भारत ने बम-बंदूक के बजाय शांति-वार्ता के जरिये समाधान की बात दोहराई। मोदी ने साहस एवं निर्भयता से पुतिन को दो टूक कहा था कि यह युग युद्ध का नहीं। चूंकि भारतीय प्रधानमंत्री की मास्को यात्रा के मौके पर ही रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में बच्चों के अस्पताल को भी निशाना बनाया, इसलिए उन्होंने बिना किसी संकोच यह भी कह दिया कि युद्ध या संघर्ष अथवा आतंकी हमलों में जब मासूम बच्चों की मौत होती है तो हृदय छलनी हो जाता है। देखना यह है कि यूक्रेन युद्ध पर भारतीय प्रधानमंत्री की फिर से खरी बात पर रूसी राष्ट्रपति कितना ध्यान देते हैं।

राष्ट्रीय दलों की परजीवी राजनीति

राज कुमार सिंह

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को एक नया नाम दिया 'परजीवी'। 18वीं लोकसभा के चुनाव परिणामों के हवाले से मोदी ने बताया कि कांग्रेस अपने बल पर नहीं, बल्कि सहयोगी दलों के दम पर आगे बढ़ी है। बेशक इन चुनावों में कांग्रेस 52 से 99 सीटों तक पहुंची, तो उसमें 'इंडिया' गठबंधन के घटकों के बीच तालमेल का बड़ा योगदान है। जिस उत्तरप्रदेश में कांग्रेस पिछली बार रायबरेली की सीट पर सिमट गई थी, समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लड़ी 8 सीटों में से 5 जीत गई। गठबंधन किए ही परस्पर लाभ के गणित के आधार पर जाते हैं। परस्पर स्वार्थ पर बने रिश्ते तभी तक चल पाते हैं, जब तक दोनों का स्वार्थ सिद्ध होता है। यह भी सच है कि अक्सर बड़े दल छोटे दलों को निगल जाते हैं, वर्ना कमजोर अवश्य करते हैं। इस मामले में कोई भी राष्ट्रीय दल अपवाद नहीं।

चुनाव के तुरंत बाद पुराने रिश्ते तोड़ नए रिश्ते बनाने के उदाहरण भी हैं। अब भाजपानीत राजग में भाजपा के बाद जो तेलुगू देशम पार्टी दूसरा बड़ा दल है, वह कभी तेलुगू सिनेमा के सुपर स्टार एन.टी. रामाराव ने बनाई थी। जनता के जबरदस्त समर्थन से वह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। एन.टी.आर. के निधन के बाद दामाद चंद्रबाबू नायडू पर तेदेपा पर कब्जा करने के आरोप लगे और उनकी विधवा लक्ष्मी पार्वती ने अलग एन.टी.आर. तेदेपा बना ली। 1998 के चुनाव भाजपा ने उसी एन.टी.आर. तेदेपा से गठबंधन कर लड़े थे, लेकिन जब परिणाम चंद्रबाबू नायडू की तेदेपा के पक्ष में गए तो पुराना रिश्ता तोड़ नया रिश्ता बनाने में देर नहीं लगाई क्योंकि गठबंधन का मकसद आंध्र प्रदेश में अपने पैर जमाना था। नायडू से भाजपा की दोस्ती लंबी चली।

अहं के टकराव के चलते बीच में टूटी तो राजनीतिक जरूरतों ने फिर साथ ला दिया। अब दोनों ही रिश्ते में जैसी गर्मजोशी दिखा रहे हैं, उसे देख कर कोई विश्वास नहीं कर सकता कि 2018 के बाद ये ही परस्पर आरोप-प्रत्यारोप में न्यूनतम शिष्टाचार की भी सीमाएं लांघ गए थे। दरअसल राजनीति, अब 'राज' की 'नीति' भर बन कर रह गई है। राज जैसे भी मिले और फिर बना रहे इसी उद्देश्य से तमाम राजनीतिक कवायद की जाती है। बिहार का उदाहरण भी देख लीजिए। 1996 में जब भाजपा के विरुद्ध राजनीतिक अस्पृश्यता चरम पर थी, तब जॉर्ज फर्नांडीज के नेतृत्व वाली समता पार्टी ने प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी के समर्थन का जोखिम लिया था। उसी समता पार्टी का नया नामकरण जनता दल यूनाइटेड हुआ।

इस लिहाज से जद-यू भाजपा के सबसे पुराने राजनीतिक मित्रों में से है, लेकिन नीतीश कुमार के 2 बार अलगाव के समय दोनों ही दलों ने एक-दूसरे के प्रति जिस गलत शब्दावली का इस्तेमाल किया, वह तो सामान्य व्यवहार में भी उचित नहीं मानी जाती, लेकिन बदलती राजनीतिक जरूरतों के बीच बार-बार रिश्ते भी निस्संकोच बदलते रहे। जद-यू को कमजोर करने के आरोप भी भाजपा पर लगे। 2020 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन के बावजूद जद-यू के उम्मीदवारों को हराने के लिए चिराग पासवान की लोजपा के इस्तेमाल का आरोप खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगाया।

विधानसभा में मात्र 43 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर फिसल कर जद-यू कमजोर हुआ भी। आर.सी.पी. सिंह प्रकरण को भी जद-यू को कमजोर करने की कवायद के रूप में देखा गया, पर हाल के लोकसभा चुनावों से कुछ ही पहले फिर जद-यू और भाजपा फिर दोस्त बन गए। बाल ठाकरे की शिवसेना भी भाजपा के पुराने मित्रों में रही। महाराष्ट्र की राजनीति में भाजपा, शिवसेना के सहारे ही आगे बढ़ी। भाजपा जूनियर पार्टनर थी, इसलिए जनादेश मिलने पर मुख्यमंत्री पद शिवसेना को मिलता रहा और भाजपा को उप-मुख्यमंत्री पद। बाल ठाकरे के निधन के बाद भी शिवसेना से भाजपा का गठबंधन तो बना रहा, पर महत्वाकांक्षाएं बढ़ गईं जिनका परिणाम 2019 में अलगाव के रूप में आया। उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि चुनाव से पहले अढ़ाई-अढ़ाई साल के मुख्यमंत्रित्वकाल पर समझौता हुआ था, लेकिन भाजपा ने उससे साफ इंकार कर दिया। शरद पवार के तो ठाकरे परिवार से पुराने रिश्ते हैं, पर भाजपा से रिश्तों में आई तल्खी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उद्धव ने उस कांग्रेस से भी हाथ मिला लिया, जिसके विरुद्ध बाल ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी। तल्खी एकतरफा नहीं थी। जो भाजपा उद्धव को अढ़ाई साल के लिए मुख्यमंत्री पद देने को तैयार नहीं हुई, उसी ने शिवसेना तोड़ कर बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनवा दिया।जद (यू) और शिवसेना की तरह शिरोमणि अकाली दल भी भाजपा का पुराना मित्र रहा। अटल बिहारी वाजपेयी और प्रकाश सिंह बादल ने जिस दोस्ती की बुनियाद रखी, वह पंजाब में दशकों चली। अकाली दल और भाजपा ने पंजाब में गठबंधन सरकार चलाई और केंद्र में भी भागीदार रहे, लेकिन महत्वाकांक्षाओं के टकराव से रिश्ते कमजोर होने लगे।

जिन नवजोत सिंह सिद्धू ने भाजपा में रहते हुए बादल परिवार के विरुद्ध मोर्चा खोला था, वह तो अंततः कांग्रेस में चले गए, लेकिन विवादास्पद कृषि कानूनों के विरुद्ध किसान आंदोलन से अकाली दल को राजग छोडने का मौका मिल गया। पिछले कुछ सालों से अकाली दल में तो असंतोष और बगावत देखने को मिली है, वह सुखबीर सिंह बादल की नेतृत्व क्षमता का संकेत तो हरगिज नहीं, पर उसके तार भाजपा से भी जोड़े जाते रहे हैं। इन लोकसभा चुनाव से पहले तेदेपा की तरह अकाली दल से भी फिर हाथ मिलाने की कोशिश की गई, लेकिन अविश्वास की खाई पाटी नहीं जा सकी। जाहिर है, छोटे दलों का इस्तेमाल करने में कोई भी राष्ट्रीय दल संकोच नहीं करता। कई राज्यों में बड़े दल सरकार बनाते ही सबसे पहले समर्थक छोटे दलों को ही तोड़ते हैं। इस लिहाज से पश्चिम बंगाल में 3 दशक से भी ज्यादा समय तक शासन करने वाला वाम मोर्चा अपवाद रहा, जिसमें किसी दल ने दूसरे दल को तोडने की कोशिश नहीं की। शायद इसलिए कि उसका आधार समान विचारधारा थी। वैसे कई बार पासा पलट भी जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस की कमजोरी को कई प्रेक्षक उन क्षेत्रीय दलों से गठबंधन का परिणाम भी मानते हैं, जिन्होंने उसका जनाधार छीन लिया।

एकात्मता के स्वर — स्वर

इस सृष्टि की उत्पत्ति नाद के साथ हुई है। उस नाद का प्रतीक है जिसे नादब्रह्म कहा गया है। भगवान् श्रीकृष्ण भगवद्गीता में कहते हैं गिरामस्म्येकमक्षरम् ।। 10/25 अर्जुन: शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार मैं हूँ। योगदर्शन में महर्षि पतंजलि ने तस्यवाचक: प्रणव: ।। 1/27 कहा है। यही नाद सृष्टि में विभिन्न रूपों से अभिव्यक्त होने वाला मनुष्यों में वाणी के रूप में व्यक्त होता है। महर्षि पाणिनि ने वाणी के चार पाद बताये हैं। परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी। ध्वनि का मूल आधार आत्मा है जहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। इसे ही परावाणी कहा जाता है। वहाँ से आत्मित भाव बुद्धि की सहायता से कर्ता के मन-पटल पर कर्म या क्रिया का चित्र देखता है वाणी का वह स्वरूप पश्यन्ती कहलाता है। इसके आगे विचार शब्दरूप बनकर नि:श्वास की सहायता से कण्ठ तक आता है यही मध्यमावाणी कही गयी है। उक्त तीनों रूप दूसरों को सुनाई नहीं देते हैं आगे यही विचार पंच स्पर्श स्थानों की सहायता से भिन्नाभिन्न रूप में वाणी द्वारा अभिव्यक्त होता है तो वही कानों से सुनाई देने वाली वाणी वैखरी कहलती है। इस वाणी द्वारा ही जीवन का सारा व्यवहार होता है। क वर्ग कंठव्य, च वर्ग तालव्य, ट वर्ग मूर्धन्य, त वर्ग दन्तव्य तथा प वर्ग ओष्ठ्य कहे गये हैं। जिनकी सहायता से ध्वनि को शब्द का रूप दिया जाता है। महाभारत में सात स्वरों की चर्चा की गई है। षड्ज ऋषभगान्धारी मध्यमों धैवस्तथा। पंचमश्चापि विज्ञेयस्तथा चापि निषादवान् ।। शांतिपर्व 184/36 यानी षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंचम, धैवत तथा सातवाँ निषाद है। सारेगमपच नी ये संगीत शास्त्र में सात स्वर माने गये हैं। स्वर उदात्त (उच्चस्वर), अनुदात्त (नीचा स्वर) और स्वरित (मध्यम स्वर) कहा गया है। नि ग जहाँ उदात्त स्वर है वहीं रे धा अनुदात्त समपये स्वरित कहे गये हैं। मनुष्य की चलने वाली श्वास को भी स्वर कहा गया है। बायाँ (इडा-चंद्र), दायाँ (पिंगला-सूर्य) तथा मध्य में सुषुम्णा कहा जाता है। वाम नाडी अमृत रूप होकर जगत को आप्यायित करती है वही दक्षिण नाडी रौद्ररूप गुण से जगत का शोषण करती है। ये दोनों प्रवाह यदि समान हो जायें तो मृत्यु आ पहुँचती है।

पुराण दिग्दर्शन ....

पुराण-परिचयाध्याय (भाग-4)

गतांक से आगे...

यह लक्षण वर्तमान पुराण-ग्रन्थों में सर्वथा घटित होता है। संसार की किसी भी भाषा में पुराणों के समान सृष्टि-विषय-विधायक, सर्वतो- मुख ग्रन्थ देखने में नहीं आता। संस्कृत साहित्य में भी पुराणों को छोड़ कर अन्य किसी ग्रन्थ में इस प्रकार का सुसम्बद्ध एवं वैज्ञानिक सृष्टिक्रम विस्तारपूर्वक नहीं मिलता। इसलिये पुराण शब्द का वास्तविक अर्थ ही इस बात का सब से बड़ा प्रमाण है कि ये ग्रन्थ पुराने से पुराने- यहां तक कि मनुष्यादि प्राणियों की उत्पत्ति-काल से भी पूर्वतम- रहस्यों का प्रत्यक्ष की भांति वर्णन करते हैं।

सूर्य्य, चन्द्र आदि ग्रह, अश्विनी आदि नक्षत्र, तारे सितारे और सैय्यारे-कब ? कैसे ? किस प्रकार बने? - यह सब बातें केवल पुराणों से ही जानी जा सकती हैं। इतने पर भी जो लोग पुराणों को नवीन कहने का दु. साहस करते हैं, वे न केवल पुराणों के प्रतिपाद्य विषय से ही अपरिचित हैं बल्कि पुराण शब्द की व्युत्पत्ति से और इसके साधक व्याकरण सूत्रों से भी सर्वथा अनभिज्ञ ही समझने चाहियें । सृष्टि की उत्पत्ति के समय से आरम्भ करके प्रलयकाल पर्यन्त ब्रह्माण्ड का क्रमबद्ध इतिहास बताने अले, तथा इस लम्बे अर्से के बीच ब्रह्माण्ड में जो तात्त्विक परिवर्तन हुए या होंगे उन सबका वैज्ञानिक किन्तु सरल और विश्वस्त वर्णन करने वाले एवं आर्य्य-संस्कृति की सजीव-मुंहबोलती-प्रतिमाओं के मणि-मँदिर, विरोधी भी जिनके चमत्कारों से विमुग्ध होकर सहसा उन्हें वास्तविक विश्वकोष कहने के लिए विवश होते हैं उन सर्व-गुण-सम्पन्न पुराणों के नाम नीचे लिखे जाते हैं- (श्रीभागवत 12। 7। 23-24) (1) ब्रह्म (2) पद्म (3) विष्णु (4) शिव (तायु) (5) लिङ्ग (6) गरुड़ (7) नारद (8) भागवत (6) अग्नि (10) स्कन्द (11) भविष्य (12) ब्रह्मवैवर्त (13) मार्कण्डेय (14) वामन (15) वाराह (16) मत्स्य (17) कूर्म और (18) ब्रह्माण्ड - यह सब अठारह पुराण हैं।

विश्व पेपर बैग दिवस

आरती राय

विश्वभर में प्रतिवर्ष 12 जुलाई के दिन को वर्ल्ड पेपर बैग डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिवस पर दुनियाभर में लोगों को प्लास्टिक बैग को छोड़कर पेपर बैग के इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा दिया जाता है और लोगों को पेपर बैग की ओर से शिफ्ट होने को लेकर प्रेरित किया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक बैग के उपयोग से पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। इसी से बचने के लिए और पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने के लिए इस दिन को मनाया जाता है।

पेपर बैग्स का इस्तेमाल इन दिनों लेटेस्ट ट्रेंड बन गया है। पर्यावरण की स्थिति को देखते हुए अब प्लास्टिक बैन कर दिया गया है और पेपर बैग्स एक अच्छे विकल्प के रूप में सामने आए हैं। पेपर बैग देखने में सुंदर लगते हैं। अलग-अलग रंग और आकार में उपलब्ध होते हैं। ये बायोडिग्रेडेबल हैं और प्लास्टिक बैग की तुलना में इनकी रीसाइक्लिंग के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है ।

एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में पेपर बैग बाजार में सालाना लगभग 4.1% की वृद्धि हुई है। अनुमान है कि 2022-2030 के दौरान पेपर बैग का बाजार 7.3 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। पेपर बैग की मेकिंग में बहुत कम लागत लगती है, इसलिए इसका बिजनेस स्टार्टअप के लिए अच्छा मौका है। 2030 तक शहरी क्षेत्रों में प्रतिष्ठित ब्रांड्स के अलावा छोटे क्षेत्रों जैसे कपड़े की दुकान, आभूषण स्टोर, बेकरी, किराना दुकानें, सब्जी की दुकानें, स्नैक्स स्टोर, मिठाई की दुकानें आदि ने भी पेपर बैग का उपयोग करना शुरू कर दिया है। ऐसे में इस उद्योग में काफी स्कोप भी है।

आज के समय में भारत दुनिया भर में बड़े पैमाने पर पेपर बैग और इनसे बने और प्रोडक्ट्स का बड़ा निर्यातक है। भारत हर साल विकसित देशों को सालाना लगभग 400 करोड़ रुपये के पेपर बैग्स और अन्य पेपर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। पेपर उत्पादों में पेपर प्लेट्स, पेपर बैग्स, पेपर कप्स, पेपर बाउल्स और बहुत कुछ शामिल हैं।

पेपर बैग के इतिहास का पता 19वीं शताब्दी से लगाया जा सकता है। 1852 में अमेरिकी अविष्कारक फ्रांसिस वोले ने पहली पेपर बैग मशीन का अविष्कार और पेटेंट कराया था। लगभग दो दशक बाद 1971 में, मार्गरेट-ई-नाइट ने एक ऐसी मशीन का अविष्कार किया जो फ्लैट-बॉटम बॉक्सी पेपर बैग का उत्पादन कर सकती थी। नाइट को The Mother Of The Grocery Bag के रूप में जाना जाने लगा। 1883 में चार्ल्स स्टिलवेल ने पेपर बैग में प्लीटेड साइड्स जोड़े। इसके बाद वाल्टर और लिडिया ड्यूबनेर ने 1912 में पारंपरिक पेपर बैग में एक लूप में तार जोड़कर पहला हैंडल वाला पेपर शॉपिंग बैग बनाया। ड्यूबनेर ने अपने अविष्कार के लिए एक पेटेंट भी जीता और शॉपिंग बैग के पूर्णकालिक निर्माता बन गए।

फ्रांसीसी चुनाव : 'लैफ्ट'-'लिबरल' का सच

बलबीर पुंज

'लैफ्ट -लिबरल' कितना विरोधाभासी है, उसका जीवंत उदाहरण फ्रांस के हालिया संसदीय चुनाव में देखने को मिल जाता है। जब पहले चरण के चुनाव में दक्षिणपंथी 'नैशनल रैली' गठबंधन ने वामपंथी दलों के ऊपर निर्णायक बढ़त बनाई और उसकी प्रचंड जीत की संभावना बनने लगी, तब इसी 'लैफ्ट-लिबरल' गिरोह के चेहरे से 'लिबरल' मुखौटा एकाएक उतर गया। वास्तव में, 'लैफ्ट-लिबरल' संज्ञा किसी फरेब से कम नहीं। यह 2 अलग शब्दों को मिलाकर बना है, जिनका रिश्ता पानी-तेल के मिलन जैसा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां वामपंथ होता है, वहां उसके वैचारिक चरित्र के मुताबिक हिंसा, असहमति का दमन, मानवाधिकारों का हनन और अराजक व्यवस्था की भरमार होती है।

ठीक इसी तरह वामपंथ और एकेश्वरवादी दर्शन का गठजोड़ भी छलावा है। ऐसे में एक 'लैफ्ट' का 'लिबरल' होना असंभव है। इस पृष्ठभूमि में फ्रांस का घटनाक्रम महत्वपूर्ण हो जाता है। फ्रांसीसी संसदीय चुनाव के पहले चरण में लैफ्ट पार्टियों के 'न्यू पॉपुलर फ्रंट' के पिछडने के बाद लैफ्ट ने 'एंटीफा' (वामपंथी समूह) और जेहादियों के साथ मिलकर ड्क्षहसक प्रदर्शन शुरू कर दिया। वे अपने खिलाफ आए इस जनादेश को मानने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने सड़कों पर कब्जा करके कई निजी-सार्वजनिक संपत्तियों को पैट्रोल-बम के इस्तेमाल से राख कर दिया, तो सुरक्षा में तैनात सैंकड़ों पुलिसकर्मियों पर टूट पड़े। इस दौरान दंगाइयों ने कई दुकानों को भी लूट लिया, उनमें तोडफ़ोड़ की और स्थानीय भवनों को बदरंग कर दिया।

अधिकतर फ्रांसीसी राजनीतिक विश्लेषक इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि राष्ट्रवादी दल की नेता मरीन ले पेन के नेतृत्व में 'नैशनल रैली' और उसके सहयोगी 250-300 सीट जीत सकते हैं। उनका यह अनुमान इसलिए भी ठीक लग रहा था, क्योंकि इसी वर्ष हुए यूरोपीय चुनाव में भी मरीन नेतृत्व ने शानदार प्रदर्शन किया था। लेकिन 'नैशनल रैली' को किसी भी सूरत में रोकने के लिए पहले चरण अलग-अलग चुनाव लडने वाले फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों नीत मध्यमार्गी 'इनसैंबल' और वामपंथी 'न्यू पॉपुलर फ्रंट' ने दूसरे चरण के आखिरी वक्त में गठबंधन (रिपब्लिकन फ्रंट) कर लिया। इसके तहत दोनों ने मिलकर अंतिम समय में अपने कुल 217 उम्मीदवारों को मैदान से हटा लिया, ताकि दक्षिणपंथ विरोधी वोट एकजुट रहे। परिणामस्वरूप, नाटकीय मोड़ के साथ 'नैशनल रैली' ऐसी पिछड़ी कि वह पहले से सीधे तीसरे स्थान पर खिसक गई।

भले ही दक्षिणपंथी 'नैशनल रैली' चुनाव हार गई, परंतु उसे सर्वाधिक 37.1 प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ, तो उसके विरोधी लैफ्ट गठजोड़ और मैक्रों नीत 'इनसैंबल' का मतप्रतिशत क्रमश: 26.3 प्रतिशत और 24.7 प्रतिशत ही रहा। फ्रांस की 577 सदस्यीय नैशनल असैंबली (संसद) में तीनों प्रमुख गठबंधनों में से किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। फ्रांसीसी गृह मंत्रालय द्वारा जारी नतीजों के मुताबिक, वामपंथी 'न्यू पॉपुलर फ्रंट' सबसे ज्यादा 188 सीट, तो मध्यमार्गी 'इनसैंबल' को 161 सीट और दक्षिणपंथी 'नैशनल रैली' 142 सीट जीतने में सफल रही है। भारत में भी 'लैफ्ट-लिबरल' का पाखंड फ्रांस से अलग नहीं है। यहां कांग्रेस के शीर्ष नेता और लोकसभा में नेता-प्रतिपक्ष राहुल गांधी को इसी श्रेणी में रखना, गलत नहीं होगा। वे विशुद्ध वामपंथी की तरह 'जितनी आबादी, उतना हक' नारा लगाते हुए 'ड्क्षहदुस्तान के धन' को पुर्नवतरित करने की बात चुके हैं। इस संबंध में 31 मार्च 2024 को दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी दलों की 'लोकतंत्र-संविधान बचाओ' रैली में राहुल के उस वक्तव्य को याद करना स्वाभाविक हो जाता है, जिसमें उन्होंने देश को ड्क्षहसा की आग में झोंकने का ऐलान किया था। तब उन्होंने कहा था, ''मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो... अगर ड्क्षहदुस्तान में मैच फिक्सिंग कर चुनाव भाजपा जीती और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा, याद रखो... ये देश नहीं बचेगा।'' दोबारा फ्रांसीसी चुनाव की ओर लौटते हैं। फ्रांस में मरीन ले पेन को उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों द्वारा यहूदी विरोधी और मुस्लिम विरोधी के रूप में पेश किया जाता है। मरीन फ्रांसीसी सैकुलर मूल्यों और राष्ट्रीय पहचान की रक्षा के लिए आप्रवासियों द्वारा बढ़ते अपराध के खिलाफ आक्रामक रही है। इसमें अक्तूबर 2020 में प्रवासी मुस्लिम द्वारा फ्रांसीसी शिक्षक का 'सिर तन से जुदा' करने की घटना भी शामिल है। अब जो वाम-जिहादी समूह पहले चरण के फ्रांसीसी चुनाव में हारने पर हिंसक हो गया था, वे दूसरे चरण के चुनाव में बढ़त बनाने के बाद हाथों में फिलिस्तीनी झंडा लेकर सड़कों पर उतरे और अराजकता फैलाने लगे।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, वामपंथी गठजोड़ द्वारा आयोजित कई 'विजय समारोहों' में फ्रांसीसी ध्वजों-झंडों की तुलना में फिलिस्तीनी झंडे फहराते और 'गाजा-गाजा' नारे लगाते देखे गए थे। वर्ष 1991 में वामपंथ नीत सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में अमरीका और यूरोप सहित सत्ता के कई केंद्र बन चुके हैं जिसमें एक अत्यंत शक्तिशाली 'राज्यहीन' और 'बिना उत्तरदायित्व' वाला समूह भी शामिल है। किसी उपयुक्त संज्ञा के अभाव में इस वर्ग को 'वोक' (2शब्द) कह सकते हैं।

यह समूह छोटा, अति-मुखर और आक्रामक है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी सरकारों को उसके उन घोषित एजैंडे को लागू करने से रोकने और व्यवस्था को पंगु करने का प्रयास करता है। स्वघोषित 'लैफ्ट-लिबरल' और 'वोक' मानकर चलते हैं कि शेष समाज निर्णय लेने में गैर-काबिल है, इसलिए उन्हें ही उनका भला करने का दैवीय अधिकार प्राप्त है। पूरे विश्व में लोकतंत्र और बहुलतावादी संस्कृति को खतरा है, तो वह दोहरे चरित्र वाले 'लैफ्ट-लिबरल' से है। कोई हैरानी नहीं कि दुनिया में जहां-जहां 'लैफ्ट' की सरकार बनी, वहां की उदारवादी व्यवस्था पर आघात हुआ और अंततोगत्वा वह समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के हनन के प्रतीक बन गया। भारत की कालजयी उदारवादी परंपराओं को इसी 'लैफ्ट-लिबरल' और 'वोक' से भी सर्वाधिक खतरा है।

आज का इतिहास

1874 ओन्टारियो कृषि कॉलेज की स्थापना की गयी।
1912 'क्वीन एलिजाबेथ' अमेरिका में प्रदर्शित होने वाली पहली विदेशी फिल्म बनी।
1917 विजिलेंस ने जबरन 1,300 हड़ताली खदान मजदूरों, उनके समर्थकों और बिसबे, एरिज़ोना, अमेरिका से न्यू मैक्सिको के निर्दोष दर्शकों को खदेड़ दिया।
1918 टोकायाम की खाड़ी में जापानी युद्धपोत में विस्फोट हुआ। जिसमें 500 लोगों की मौत हुई।
1918 जापानीबटलशिप कावाची की गोला बारूद पत्रिका में विस्फोट से 600 से अधिक अधिकारी और क्रू के लोग मारे गए।
1920 सोवियत संघ और लिथुआनिया के बीच सोवियत-लिथुआनिया संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। सोवियत संघ द्वारा लिथुआनिया को एक संप्रभु देश के रूप में मान्यता दी गई थी।
1920 सोवियत-लिथुआनियाई शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, सोवियतरसिया ने एक स्वतंत्र लिथुआनिया को मान्यता देने के लिए सहमति व्यक्त की थी।
1935 बेल्जियम ने कूटनीतिक रूप से सोवियत संघ को मान्यता दी।
1939 त्रिनिदाद और टोबैगो रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई।
1943 प्रोखोरोव्का की लड़ाई हुई। यह सोवियत संघ और जर्मनी की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लड़ा गया था। लड़ाई सोविएत संघ की भूमि पर हुई।
1943 द्वितीय विश्व युद्ध-जर्मन और सोवियत सेनाओं ने प्रोकोरोव्का की एक-दूसरे की लड़ाई में भाग लिया, जो मिलिटहिस्टोर (सोवियत टी -34 टैंक चित्र) में सबसे बड़ी टैंक लड़ाइयों में से एक थी।
1948 इजरायल के पीएम ने इजरायली शहरों लोद और रामला से सभी फिलिस्तीनियों को निष्कासित करने का आदेश दिया। यह घटना इज़राइल-अरब युद्ध के दौरान हुई थी।
1948 अरब-इजरायल युद्ध-इजरायल रक्षा बल के अधिकारी यित्जाक रबिन्स ने फिलिस्तीनियों को लोद और रामला के शहरों से निष्कासित करने का आदेश दिया।
1962 ब्रिटिश रॉक बैंड द रोलिंग स्टोन्स ने लंदन में मार्की क्लब में अपना पहला संगीत कार्यक्रम खेला।

भगवान राम, अयोध्या व सनातन को कोई कभी समाप्त कर ही नहीं सकता

मृत्युंजय दीक्षित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में विकसित भारत के संकल्प के साथ काम में जुट गए हैं और विपक्ष अभी भी तीसरी पराजय की हताशा में डूबा चुनावी मोड में दिख रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व में सम्पूर्ण विपक्ष के नेता सप्ताह में दो बार सरकार गिरने की भविष्यवाणी करके सनसनी फैलाने और मीडिया की फुटेज खाने का प्रयास करते रहते हैं। वर्तमान लोकसभा में कुछ सीटें अधिक आने से कांग्रेस का दिमाग सातवें आसमान पर है। जब से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के रूप में स्थान मिला है, कांग्रेसी हर दिन मोदी सरकार अब गिरी तब गिरी के सपने देख रहे हैं।

नई सरकार के गठन के बाद पहले संसद सत्र में मोदी सरकार ने जिस कुशलता के साथ विपक्ष के प्रत्येक दांव को ध्वस्त किया उससे विपक्ष बुरी तरह तिलमिला गया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ने पहले लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव पर सरकार को घेरने और उसमें मतदान कराकर गिराने का सपना देखा और फिर नीट पेपर लीक घोटाले पर बहस करने को लेकर अड़ गया किंतु दोनों ही जगह वह मात खाया। यानि संसद के पहले सत्र में विपक्ष ने अनावश्यक रूप से सरकार को गिराने व घरेने का प्रयास किया और विफल रहा।

संसद सत्र में कमजोर दिखने के बाद विपक्ष के तेवर और तीखे हो गये हैं वह सच्ची-झूठी बातों को लेकर सरकार आरोप लगा रहा है। सोशल मीडिया स्वयं प्रियंका गाँधी ने ऐसे वीडियो डाले जो फेक थे। वास्तविक मुद्दों से अधिक विपक्ष झूठ फैलाने में सक्रिय है। बारिश में पानी भरने के लिए भी केंद्र सरकार को कोसा जा रहा है और ब्राज़ील का वीडियो रामपथ के नाम से पोस्ट किया जा रहा है। विपक्ष को लगता है इस तरह झूठ फैलाने से मोदी सरकार की छवि प्रभावित हो जाएगी और उसको गिरना सरल होगा।

राहुल गांधी सक्रियता के नाम पर आवेश दिखा रहे हैं। उन्होंने लोकसभा की 543 में से 99 सीटों पर सफलता प्राप्त की है और उनका अहंकार इतना अधिक बढ़ गया है कि वह जितनी बार मुंह खोलते हैं उतनी बार हिंदू समाज व उसकी आस्था के प्रतीकों का अपमान करते हैं फिर चाहे वो संसद के अंदर हो या बाहर। जहां जहां कोई दुर्घटना या सामाजिक समस्या है वहां वहां राहुल गांधी का काफिला अपनी राजनीति चमकाने जा रहा है। राहुल अभी तक हाथरस, मणिपुर और असम जाकर अपनी मोहब्बत की दुकान का प्रचार कर चुके हैं। समस्या कोई भी हो, स्थान कोई भी हो राहुल चर्चा केवल मोहब्बत की दुकान

की ही करते हैं, इस बीच कोई पत्रकार प्रश्न पूछ ले तो उनके तेवर बदल जाते हैं और वो गुस्से में पैर पटक कर चल देते हैं।

सोनिया के समय हिन्दुओं के प्रति कांग्रेस दबी ढकी नफरत राहुल के समय खुल कर सामने आ गई है। राहुल गांधी ने संसद में अपने पहले ही भाषण में सम्पूर्ण हिंदू समाज को हिंसक कहने का दुस्साहस किया। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी ने जोर देकर इस बात को दोहराया किङ्क जो अपने को हिन्दू कहते हैं वो हिंसक होते हैं। सदन में प्रधानमंत्री जी ने इसका तत्क्षण इसका प्रतिवाद किया और बाद में अपने संबोधन में भी इस पर विस्तार से चर्चा की तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग हंगामा करते रहे। राहुल गांधी ने अपमानजनक तरीके से भगवन शिव का चित्र लहराया और उनके स्वरुप की गलत विवेचना करी। सदन के बाहर विरोध होने पर कांग्रेस ने एक बार झूठ का सहारा लेकर मामले पर लीपा पोती करने का प्रयास किया। नेता प्रतिपक्ष के रूप में पहली बार गुजरात पहुंचे राहुल गांधी इतने अधिक उत्साह में थे कि वह वाराणसी में ही प्रधानमंत्री मोदी को निपटा देते जैसी शब्दावली का प्रयोग करने लगे। राहुल यहीं नहीं रुके, आगे बढ़ते हुए बोले गुजरात से लालकृष्ण आडवाणी ने जो मूवमेंट चलाया था उसे हमने अयोध्या में हरा दिया है। स्पष्ट है राहुल गाँधी को न तो श्री रामजन्मभूमि मुक्ति यज्ञ का इतिहास पता है, न उनमें हिन्दुओं की आस्था के प्रति सम्मान है। राहुल गांधी ने गुजरात में अपने भाषण के माध्यम से हिंदू समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उन्होंने कांग्रेस की कुछ सीटें बढ़ाकर बड़ी गलती कर दी है। राहुल के इस बयान से कांग्रेस की वामपंथी मुस्लिम परस्त मानसिकता ही बेनकाब हुयी है।

आजकल राहुल और अखिलेश फैजाबाद के सांसद को तमगे की तरह साथ लेकर घूमते हैं, उनको अयोध्या का राजा बताते हैं और सनातन समाज का मखौल उड़ाते हैं। यदि इन दोनों को लग रहा है कि अयोध्या में भाजपा को हराकर उन्होंने हिन्दुत्व को हरा दिया है तो यह उनकी बहुत बड़ी भूल है। इनको लग रहा है कि अब लोग न तो जय श्रीराम का नारा लगाएंगे और न ही अयोध्या में श्रीराम का दर्शन करने आयेंगे लेकिन उन्हें नहीं पता कि भगवान राम भारत की आत्मा और सनातन धर्म का मूल हैं।

दो लड़कों की जोड़ी को यह बात समझनी चाहिए कि भगवान राम, श्रीकृष्ण और भगवान शिव भारत की आत्मा हैं और इनका सार्वजनिक उपहास बहुत दिनों तक नहीं बनाया जा सकता। राहुल गांधी के बयानों को सुन सुनकर हिंदू समाज मन ही मन कुढ़ रहा है और अपनी गलती पर सिर धुन रहा है। वहीं संत समाज राहुल को अयोध्या में नहीं घुसने देना चाहता। राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के नेताओं को यह बात अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि लोकतांत्रिक देश के चुनावों में जय-पराजय तो होती ही रहती है किंतु राष्ट्रीय आस्था कभी नहीं बदलती। हिंदू समाज ने श्री रामजन्म भूमि को विधर्मियों से मुक्त कराने के लिए 77 बार भीषण संघर्ष किया और सर्वस्व बलिदान करते हुए अंततः विजय प्राप्त की इस विजय का उपहास कर रहे हैं ये लोग।

अयोध्या अपराजिता है विधर्मी उस पर आक्रमण कर सकते हैं जीत नहीं सकते, अयोध्या यश से परिपूर्ण है, दुःखों का हरण करने वाली है और श्रीराम के तेज से प्रकाशित है, आसुरी भावनाओं द्वारा ये कभी पराजित नहीं होगी। इस अयोध्या को इक्ष्वाकुवंश के राजाओं ने अपनी राजधानी बनाया और भगवान राम ने यहीं जन्म लिया यह शाश्वत सत्य है। भगवान राम को सृष्टि पर्यंत कोई नहीं हरा सकता। सपा ने फैजाबाद लोकसभा सीट का चुनाव जीता है और उसको राहुल गांधी विपरीत दिशा में ले जाकर प्रचारित कर रहे हैं। अयोध्या की पराजय पर तंज कसने वाले नेताओं को पता होना चाहिए कि किसी भी बात की अति बुरी होती है।

राहुल गांधी को भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी जी के राम मंदिर आन्दोलन को राजनैतिक समर्थन देने से आज भी इसलिए दर्द है क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी जी की तमाम रथयात्राएं ही हैं जिनसे कांग्रेस का हिन्दू विरोधी चेहरा सामने आया और आज भी कांग्रेस लोकसभा में 100 का आंकड़ा छूने को तरस रही है।

मुस्लिम तुष्टीकरण और झूठे विमर्श पर कुछ सीटें अधिक जीतने वाले राहुल गांधी का उतावलापन कांग्रेस व उसके सहयोगी दलों को भारी पड़ सकता है क्योंकि भगवान राम भारत की आस्था, आधार, विचार, विधान, चेतना, चिंतन, प्रतिष्ठा प्रताप और प्रवाह हैं। प्रभाव, नीति, नियति, नित्यता, निरंतरता के साथ राम विभु, विषद और व्यापक हैं और हर सनातनी जानता हैङ्क जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिये ताहि कोटि बैरी सम जद्दपि परम सनेही।

वाम दिशा में आखिर क्यों चल पड़ा ब्रिटेन?

रहीस सिंह

ब्रिटेन में कंजरवेटिव राज खत्म हुआ और सेंटर-लेफ्ट लेबर पार्टी कीर स्टार्मर के नेतृत्व में भारी बहुमत के साथ सत्ता में आ गई। सवाल यह है कि ब्रिटिश मतदाताओं ने कंजरवेटिव पार्टी के उन चेहरों को ठुकराया है जो जनता के दर्द समझने और उनकी समस्याओं का समाधान निकालने में अक्षम रहे हैं अथवा कारण कुछ और हैं? ब्रिटिश मतदाताओं ने एक संदेश तो अवश्य दिया है कि वे अब ग्लोबलाइजेशन और पूंजीवादी बाजारवाद की बड़ी-बड़ी बातें और विज्ञापनी दुनिया से दूर यथार्थ को जीना चाहते हैं, उसके साथ चलना चाहते हैं। तो क्या कीर स्टार्मर और उनके नेता ऐसा कर पाएंगे? क्या लेबर पार्टी उन झंझावातों से ब्रिटेन को निकाल पाएगी जिसमें पिछले 14 वर्षों में ब्रिटेन उलझता चला गया? यहां एक बात समझने की जरूरत तो है कि आखिर वह कौन सी वजह रही जिसके चलते ब्रिटेन यूरोप के उस धुर दक्षिणपंथी ढर्रे पर चलने के लिए तैयार नहीं हुआ जिस पर अधिकांश यूरोपीय देश दौड़ लगाने के लिए तैयार दिख रहे हैं? वैसे तो इस नवऔद्योगिक-नवपूंजीवादी दौर के पूंजी और बाजार की दृष्टि से दोनों ही पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं हैं। फिर यूरोप में धुर दक्षिण पंथ (फार-राइट) की हवा चल रही है तो इसका कारण है इमिग्रेशन (आप्रवासन)। इस इमिग्रेशन से ही साढ़े चार साल पहले तक ब्रिटिश मतदाताओं ने लेबर पार्टी के 'क्रासी नेशनलिस्ट' और 'क्रासी लिबरल' एप्रोच को खारिज कर कंजरवेटिव नेशनलिज्म को क्यों पसंद किया था और अब वे 180 डिग्री क्यों घूम गए? वजह क्या रही? ब्रिटेन ने यूरोप के साथ चलना क्यों पसंद नहीं किया? कंजरवेटिव राष्ट्रवाद औंधे मुंह क्यों गिर गया और क्यों हाउस ऑफ कामंस लेबर पार्टी के लाल रंग में पूरी तरह से रंगा हुआ नजर आया? वैसे परिवर्तन ब्रिटेन में ही नहीं, अब तो फ्रांस में भी दस्तक देता हुआ दिख रहा है। रविवार को फ्रांस में हुए संसदीय चुनाव में कुल 577 सीटों में से वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट (एनएफपी) गठबंधन को 182 सीटें मिलीं। जबकि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की रेनासां पार्टी 163 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। यह इस बात का संकेत है कि यूरोप इस समय संक्रमण से गुजर रहा है। चुनाव में जीत के बाद स्टार्मर ने कहा, 'अब रीसेट का समय आ गया है।' उन्होंने यह भी कहा कि हालात को बदलने में समय लगेगा लेकिन मैं एक-एक ईंट जोड़कर देश को फिर से बनाऊंगा। 'रीसेट' अच्छा और आशावादी शब्द है, यदि ऐसा संभव होता है तो ब्रिटेन वास्तव में चल पड़ेगा परंतु यह इतना आसान नहीं लगता। ऋषि सुनक और उनकी कंजरवेटिव पार्टी ने ब्रिटेन को जहां छोड़ा है, वहां से बाहर एक ऐसे 'हाई वे' तक उसे लाना जहां वह फर्राटा भर सके, बेहद मुश्किल कार्य है।

फ्रांस में गठबंधन सरकार के क्या हैं मायने

स्वर्ण सिंह

इस महीने के आखिर में शुरू हो रहे पेरिस ओलिंपिक से ठीक पहले फ्रेंच नैशनल असेंबली के आकस्मिक चुनावों के नतीजों ने फ्रांसीसी राजनीति की पुरानी दरारों को और जटिल बना दिया है। सन 1959 में जनरल डी गॉल की फ्रांस में पांचवें गणतंत्र की स्थापना से आज तक, पहली बार इस तरह के खंडित परिणामों के चलते गठबंधन सरकार का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। विधायिका के 2022 के चुनावों में भी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की पार्टी को 577 सीटों वाली संसद के निचले सदन में केवल 245 सीटें मिली थीं। लेकिन तब एक स्थिर सरकार सुनिश्चित करने के लिए रूढ़िवादी रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन मिल गया था। इस बार मैक्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी इन दलों से जूझना। उनका कार्यकाल 2027 तक है।

इस चुनाव में वामपंथी दलों का नवगठित गठबंधन 'न्यू पॉप्युलर फ्रंट' 182 सीटें जीत कर सबसे बड़े ब्लॉक के रूप में उभरा हैं। हालांकि बहुमत के आंकड़े 289 से वह बहुत दूर है। इसके बाद राष्ट्रपति मैक्रों के मध्यमार्गी गठबंधन 'एनसेंबल' की 168 सीटें हैं। कट्टर दक्षिणपंथी कही जाने वाली नैशनल रैली को हाल में हुए यूरोपीय संसद के चुनावों में और फिर इस चुनाव के पहले चरण में सबसे ज्यादा वोट मिले थे। लेकिन, वह तीसरे स्थान पर सिमट कर रह गई है। हालांकि 2022 के चुनावों में नैशनल रैली को केवल 89 सीटें मिली थीं। इस बार यह संख्या 143 है। इससे जाहिर होता है कि पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा है।

फ्रांसीसी चुनावी प्रणाली में एक उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिए 50त्न से अधिक वोट जीतने होते हैं। यदि कोई भी इस सीमा को पार नहीं करता है, तो 12.5त्न से अधिक वोट वाले उम्मीदवार दूसरे चरण में जाते हैं। इस चरण में सबसे अधिक वोट पाने वाला जीत जाता है। पहले दौर में, 50त्न वोट पाकर चुने गए 76 उम्मीदवारों में से 39 राष्ट्रीय रैली से थे। ऐसा लग रहा था कि यह पार्टी चुनाव जीतने वाली है और 28 वर्षीय जॉर्डन बार्डेला अगले प्रधानमंत्री होंगे।

सन 1972 में नैशनल रैली की स्थापना होलोकॉस्ट के आव्रजन विरोधी जीन-मैरी ले पेन ने की थी। हालांकि इस

पार्टी को मुख्यधारा में लाने का काम इस शताब्दी में उनकी बेटी मरीन ले पेन ने किया। उन्होंने 2022 के चुनावों के दौरान राष्ट्रपति पद मैक्रों से लगभग जीत लिया था। अब इसकी अध्यक्षता जॉर्डन बार्डेला कर रहे हैं। उन्होंने प्रवासन, अल्पसंख्यकों और धर्म पर अपने रुख को नरम किया है, जो आंशिक रूप से उनकी बढ़ती सामाजिक स्वीकार्यता को स्पष्ट करता है। इसीलिए, चुनाव के दूसरे चरण से पहले, 200 से अधिक मध्यमार्गी और वामपंथियों ने अपने वोट कटने से बचने के लिए नामांकन वापस ले लिया। गैर-दक्षिणपंथी वोटों का यह एकीकरण नैशनल रैली को सत्ता तक पहुंचने से रोकने में सफल रहा। विधायिका के कार्यकाल पूरा होने से तीन साल पहले ही अचानक केवल तीन हफ्ते में चुनाव कराने के पीछे मैक्रों का यही एक बड़ा मकसद था। अब राष्ट्रपति मैक्रों अपनी संवैधानिक शक्तियों से इस दल को और भी कमजोर बना सकते हैं।

अधिकांश उदार लोकतंत्रों के विपरीत, फ्रांसीसी राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकारी नहीं है कि वह नैशनल असेंबली में सबसे बड़े दल से ही अपने प्रधानमंत्री का चयन करें। संविधान राष्ट्रपति मैक्रों को अलग-अलग दलों से कैबिनेट चुनने की अनुमति देता है। लेकिन ऐसी उम्मीद की जाएगी कि वह सबसे बड़े गठबंधन 'न्यू पॉप्युलर फ्रंट' से ही अपना प्रधानमंत्री चुनें। ऐसा पहली बार नहीं होगा जब राष्ट्रपति और पीएम अलग-अलग दलों से होंगे। लेकिन इससे यह सुनिश्चित होगा कि उनकी गठबंधन सरकार को रोजमर्रा के काम में कम विरोध का सामना करना पड़ेगा।

फ्रांसीसी संविधान का अनुच्छेद 49 सरकार को बिना वोट के कानून पारित करने की अनुमति देता है। सदन के नेता के रूप में यह शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। विधायक केवल अविश्वास प्रस्ताव लाकर ही ऐसे विधेयकों को पारित होने से रोक सकते हैं। उन्हें यह केवल 24 घंटे के भीतर करना होता है और ऐसे निर्णय को रोकने के लिए उन्हें 289 वोटों की आवश्यकता होगी। साथ ही, इसके चलते सरकार भी गिर जाएगी। राष्ट्रपति मैक्रों ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान एक बार और दूसरे कार्यकाल के दौरान 11 बार इस शक्ति का उपयोग किया है।

राष्ट्रपति मैक्रों को गठबंधन के भीतर के विरोध की चिंता होगी। उदाहरण के लिए, सबसे बड़े 'न्यू पॉप्युलर फ्रंट' में समाजवादी, कम्युनिस्ट, पर्यावरण और सामाजिक न्याय वाले, कट्टर वामपंथी जीन-ल्यूक मेलेनचॉन का 'फ्रांस अनबोएड' ङ्क सब शामिल हैं। मेलेनचॉन का नाम पीएम पद के लिए न्यू पॉप्युलर फ्रंट की चर्चाओं में है। वह पहले ही इस चुनावी फैसले को राष्ट्रपति मैक्रों की नैतिक हार बता चुके हैं। उन्होंने सार्वजनिक मांग रखी है कि राष्ट्रपति को नैशनल असेंबली के सबसे बड़े ब्लॉक यानी न्यू पॉप्युलर फ्रंट से ही प्रधानमंत्री चुनना होगा।

नैशनल रैली के नेता रूस के करीबी माने जाते हैं। वामपंथी भी रूस-यूक्रेन युद्ध को जल्द समाप्त करने का आह्वान कर रहे हैं। ऐसे में मैक्रों के लिए इस जटिल विविधता में संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। अपने राष्ट्रपति पद को निष्क्रियता के लिए याद किए जाने से बचाने को उन्हें वाम और दक्षिणपंथ के उन नेताओं को ढूंढ निकलना होगा, जो उनके मध्यमार्गी रुख के साथ जुड़ सकें।

कांग्रेस शासित राज्यों में मुसलामान पिछड़े क्यों हैं?

योगेंद्र योगी

देश में अल्पसंख्यकों के विकास के बजाए भावनात्मक मुद्दों पर बरगला कर उनके दोहन का खेल जारी है। राजनीतिक दल अल्पसंख्यकों को वोट बैंक की फसल से ज्यादा कुछ नहीं समझते। अल्पसंख्यकों का अधिक हितेषी साबित करने के लिए गैरभाजपा राजनीतिक दलों में कभी खत्म नहीं होने वाली चुनावी प्रतिस्पर्धा जारी है। इसका मंच चाहे चुनावी सभाएं हो या संसद के दोनों सदन। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी का अल्पसंख्यक वोट बैंक को रिझाने के प्रयास में भाजपा पर देशभक्त अल्पसंख्यकों के खिलाफ भी हिंसा फैलाने का आरोप लगाया। राहुल ने भाजपा का नाम लिए बगैर कहा कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ और सिख लोगों के खिलाफ हिंसा और नफरत फैलाते हैं। जबकि अल्पसंख्यक हर क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं। अल्पसंख्यक देश के साथ पत्थर की तरह खड़े हैं, देशभक्त हैं और आप सबके खिलाफ हिंसा और नफरत फैलाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अल्पसंख्यकों ने देश के साथ-साथ संविधान की भी रक्षा की है। राहुल गांधी का यह बयान महज एक चुनावी बयान से अधिक कुछ नहीं है। यह पहला मौका नहीं है जब अल्पसंख्यकों के वोट बैंक के लिए संसद के मंच का इस्तेमाल किया गया हो। चुनावी सभाएं हों या संसद, मौके-बेमौकों पर अल्पसंख्यक की हिमायत करने का कांग्रेस और दूसरे गैरभाजपा दल कोई मौका नहीं छोड़ते। अल्पसंख्यकों की पैरवी करने वाली कांग्रेस और राहुल गांधी ने यह खुलासा कभी नहीं किया कि आजादी के करीब 60 साल तक कांग्रेस का शासन केंद्र और ज्यादातर राज्यों में रहने के बावजूद अल्पसंख्यक बुनियादी सुविधाओं और देश की विकास की मुख्यधारा से दूर क्यों हैं।

अल्पसंख्यकों को लेकर हायतौबा मचाने वाली कांग्रेस ने कांग्रेसशासित राज्यों में उनकी भलाई के लिए कौन से प्रयास किए। इसके अलावा केंद्र और भाजपा शासित राज्यों में सरकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों से कौनसा भेदभाव किया गया है। इसका भी खुलासा कभी कांग्रेस ने नहीं किया है। यह सही है कि भाजपा ने मुस्लिम अल्पसंख्यकों को पार्टी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया, किन्तु यह भाजपा

का आंतरिक मामला है। सरकारी स्तर पर भाजपा के मुसलमानों से भेदभाव का एक भी उदाहरण मौजूद नहीं है। जो योजनाएं देश या राज्यों के स्तर पर भाजपा सरकारों ने लागू कि उनमें सभी को पात्रता के आधार पर सुविधाएं दी गई हैं। जाति, धर्म या समुदाय के आधार पर कोई अंतर नहीं रखा गया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अनुसार साल 2014 से देश में पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले लगभग 5 करोड़ से ज्यादा छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई। सरकार का कहना है कि ऐसा करने से खासकर मुस्लिम लड़कियों के स्कूल छोडने की संख्या कम हुई है। 2014 से पहले मुस्लिम लड़कियों में स्कूल छोडने की संख्या 70 प्रतिशत थी जो अब घटकर 30 प्रतिशत से भी कम हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा सीखो और कमाओ योजना शुरु की गई। इसी योजना के तहत इस साल यानी 2022 में लगभग 8 लाख महिला को लाभ पहुंचा है। वर्ष 2021-22 में देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में मुसलमानों का कुल नामांकन 21.1 लाख रहा, जबकि 2020-21 में यह आंकड़ा 19.22 लाख और 2014-15 में 15.34 लाख था, यानी 7 वर्षों में 37.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई लेकिन कोरोना के दौरान इसमें बड़ी गिरावट आई थी। सवाल यह है कि देश में ज्यादातर वक्त राज करने के बावजूद कांग्रेस शासित राज्यों में मुसलमानों की साक्षरता दर सौ प्रतिशत क्यों नहीं हो पाई। निजी और सरकारी क्षेत्र में रोजगार विकसित करने के लिए कांग्रेस का आंकड़ा सर्वोच्च क्यों नहीं रहा।

अल्पसंख्यकों की असुरक्षा को लेकर भी कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दल उन्हें भयभीत करने का काम करते रहें हैं, ताकि उनके वोट पर अधिक हिस्सा बटोरा जा सके। भारत में 300,000 से अधिक सक्रिय मस्जिदें हैं, जो अधिकांश इस्लामिक देशों से अधिक है। जनसंख्या के मामले में भारत तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। देश के किसी भी भाजपाशासित राज्य में एक भी मस्जिद को नहीं तोड़ा गया सिवाए बाबरी मस्जिद के, जिसका फैसला भी कानून के दायरे में हुआ। मथुरा में ईदगाह कृष्ण जन्मभूमि विवाद और वाराणासी में ज्ञानव्यापी विवाद अदालत में विचाराधीन है। जबकि पिछले दस वर्षों से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। इसके बावजूद किसी भी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया गया।

मुसलमानों को देशभक्त बताने वाले राहुल गांधी और कांग्रेस ने इस पर भी कभी प्रतिक्रिया नहीं दी कि केंद्र में मोदी सरकार सरकार आने के बाद देश में आतंकियों द्वारा किए जाने वाले बम धमाके कैसे रुक गए। इन बम धमाकों के आरोपियों के लगभग सभी नाम मुस्लिम समुदाय से ही क्यों आए। इसके अलावा देश में होने वाले सांप्रदायिक दंगों पर लगाम कैसे लग गई। दस साल पहले तक उत्तर प्रदेश इन दंगों के लिए बदनाम था। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान होने वाले सांप्रदायिक दंगे योगी सरकार के आने के बाद कैसे रुक गए। सच्चाई यही है कि कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दलों ने मुसलमानों को डर दिखा कर उन्हें पिछड़ा बनाए रखने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। जागरुकता के इस दौर में मुसलमान भी इस सच्चाई को काफी हद तक समझ गए हैं। भाजपा को चाहिए मुसलमानों को भी पर्याप्त राजनीतिक भागीदारी दे ताकि दूसरे दलों की अल्पसंख्यकों के नाम पर वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति

प्रधानमंत्री के खिलाफ बैल बुद्धि अभियान चला कर कांग्रेस ने बालक बुद्धि का परिचय दिया है

नीरज कुमार दुबे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता जगजाहिर है। यह प्रतिद्वंद्विता चुनावों के दौरान तीखे हमलों में भी तब्दील हो जाती है। लेकिन जनता इसे सामान्य रूप में ही लेती है क्योंकि यह अपेक्षित ही है कि राजनीतिक विरोधी एक दूसरे पर हमले करेंगे ही लेकिन चिंताजनक स्थिति तब पैदा होती है जब राजनीतिक हमले शालीनता और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा को लांघ जाते हैं। कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री पर जिस तरह के हमले किये जा रहे हैं वह राजनीति में शिष्टाचार खत्म होने का संकेत तो है ही साथ ही इससे यह भी प्रदर्शित हो रहा है कि कांग्रेस को मोदी को लगातार तीसरी बार मिला सरकार चलाने का जनादेश नहीं भाया है। कांग्रेस को समझना होगा कि देश का प्रधानमंत्री किसी एक दल का नेता नहीं होता बल्कि वह समस्त भारतीयों का प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति दुनिया में भारत का चेहरा होता है। प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति से भले कितने भी वैचारिक और राजनीतिक मतभेद हों लेकिन उसका सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। साथ ही प्रधानमंत्री पर राजनीतिक हमले करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देश के संवैधानिक पद का कोई अपमान नहीं हो जाये। लेकिन खेद की बात यह है कि देश पर सर्वाधिक समय तक राज करने वाली और देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देने वाली कांग्रेस प्रधानमंत्री के पद का लगातार अपमान करने में लगी हुई है। हम आपको याद दिला दें कि जब-जब गांधी परिवार के पास प्रधानमंत्री पद रहा तब-तब ही कांग्रेस ने इसका सम्मान किया। इतिहास उठा कर देखेंगे तो पाएंगे कि लाल बहादुर शास्त्री से लेकर नरेंद्र मोदी तक...कांग्रेस को यह पचा ही नहीं कि कैसे कोई गैर-गांधी परिवार का व्यक्ति देश पर राज कर रहा है। पिछला उदाहरण डॉ. मनमोहन सिंह का है। जब डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब उनके पास सारे अधिकार ही नहीं थे। मंत्री उनकी बात नहीं सुनते थे और सारे बड़े फैसले सोनिया गांधी करती थीं। इसके बाद जबसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तबसे कांग्रेस ने उनके खिलाफ निचले और निजी स्तर पर हमले करने का अभियान चलाया। मोदी पर कांग्रेस के हमलों का जवाब जनता चुनावों में देती रही लेकिन इस बार के लोकसभा चुनावों में मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सीटें क्या घटीं, कांग्रेस के हमले और निचले स्तर पर चले गये हैं। हम आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैल बुद्धि करार देते हुए सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अभियान चलाया हुआ है जिसे कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता आगे बढ़ा रहे हैं। भले कांग्रेस ने यह अभियान प्रधानमंत्री की ओर से राहुल गांधी को बालक बुद्धि बताये जाने के जवाब में चलाया हो लेकिन उसे ध्यान रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है। संभव है कि कांग्रेस के बैल बुद्धि अभियान के जवाब में भाजपा भी कोई अभियान शुरू करे। लेकिन सवाल यह है कि इस सबसे क्या हासिल होगा? संभव है कि सोशल मीडिया पर ऐसे अभियानों को ज्यादा लाइक्स और रिपोस्ट मिल जायें लेकिन क्या ऐसे ही अभियानों से लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है। आज के नेताओं को अपने पूर्ववर्तियों से सबक लेना चाहिए जिन्होंने तमाम मतभेदों के बावजूद एक दूसरे के खिलाफ निजी हमले कभी नहीं किये और लोकतंत्र की गरिमा को बनाये रखा। बहरहाल, प्रधानमंत्री के खिलाफ बैल बुद्धि अभियान चला कर कांग्रेस ने वाकई बालक बुद्धि का परिचय दिया है।

लोकतेज
epaper.loktej.com
11 Jul 2024 - Page 5

नदी पर बनाया जाता है बर्फ का होटल, दूर-दूर से ठहरने आते हैं पर्यटक!

दुनियाभर में कई तरह के घुमक्कड़ होते हैं जो तरह-तरह की जगह जाना पसंद करते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें अजीबो-गरीब होटल देखना या वहां ठहरना भी पसंद होता है। अगर आप भी कुछ ऐसा ही शौक रखते हैं तो आज हम आपको एक ऐसे ही अजीबो-गरीब होटल के बारे में बताने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया में अपनी खासियत के लिए मशहूर है।

कुछ अलग दिखने की सूची में स्वीडन में मौजूद आइस होटल शमिल है। ये अपने हटके प्रस्तुति के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। काफी पुराना होने के बावजूद भी ये होटल अपने कलाकारी के लिए लोगों के बीच आकर्षित है। यहां हर साल कलाकार अलग-अलग कलाकारियां करते हैं। आइए आपको आइस होटल की अन्य खासियत के बारे में बताते हैं, जो आपको हैरान कर सकती हैं...

नदी पर बना हुआ होटल

स्वीडन के टॉर्न नदी के ऊपर आइस होटल बना हुआ है। ये होटल पूरी तरह से बर्फ का बना

हुआ होता है। इसकी खासियत है कि ये पिघलकर नदी का रूप ले लेता है। तय समय तक ये आइस होटल रहता है और फिर हर साल इसे बनाया जाता है। हर साल ये अलग-अलग आकर और कलाकारियों के साथ बनाया जाता है। जिसे देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं। यहां ठहरने के लिए पर्यटकों को 1 साल पहले ही बुकिंग करनी होती है।

अप्रैल के बाद पिघलना शुरु हो जाता है होटल

जब तक मौसम ठंडा और बर्फदार रहता है तब तक ये होटल अपने ठोस आकार में नदी पर मौजूद रहता है। वहीं, तापमान गर्म होने पर ये पिघलकर पानी में बदल जाता है। इसे हर साल नए-नए डिजाइन में बनाया जाता है। यहां आकार दुनियाभर के कलाकार अपनी कलाकारियां दिखाते हैं।

काफी कम तापमान के होते हैं कमरे

सोलर पॉवर कूलिंग की मदद से होटल के कमरों को बनाया जाता है। यहां ज्यादातर लाइट्स या अन्य उपकरणों को सौर ऊर्जा से ही चलाया जाता है। ये होटल इकोफ्रेंडली होने के कारण लोगों के लिए पहली पसंद में से एक है। यहां के कमरों का तापमान काफी कम होता है। बर्फ की मोटी-मोटी परत को काटकर कमरा बनाया जाता है। गर्मी आने तक ये होटल बर्फ के तौर पर रहता है और फिर अप्रैल के बाद पिघलना शुरु हो जाता है।

बर्फ के सेरेमनी हॉल और रेस्त्रां भी मौजूद

साल 1992 में पहली बार ये होटल खोला गया था। यहां मौजूद रेस्त्रां, सेरेमनी हॉल और कॉम्प्लेक्स को बर्फ से ही बनाया जाता है। इतना ही नहीं, होटल के फर्नीचर, दीवार, बार समेत अन्य चीजों को भी बर्फ से ही बनाया जाता है। यहां एक से एक डिजाइनिंग वाले कमरे मौजूद हैं।

कम से कम खर्च में घूमने के लिए अपनाएं यह टिप्स, जेब पर नहीं पड़ेगा जोर

घूमना आखिरकार किसे अच्छा नहीं लगता। हर दिन के तनाव और रूटीन से ब्रेक लेते हुए नई जगहों को एक्सप्लोर करने का अपना एक अलग ही आनंद है। लेकिन फिर भी मध्यम वर्गीय परिवार चाहकर भी घूमने नहीं जा पाते और उसकी वजह होती है बजट। चार-पांच महीने में अगर एक बार भी घूमने का प्लॉन बनाया जाए तो इससे पूरा बजट बिगड़ जाता है और सेविंग भी काफी हद तक खर्च हो जाती है। हो सकता है कि आप भी पैसों के चक्कर में घूमने ना जा रहे हों। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बता रहे हैं, जिसे अपनाकर आप ट्रेवलिंग के दौरान पैसों की भी बचत कर सकते हैं-

प्लान करें ट्रिप

जब आप किसी नई जगह पर घूमने का विचार कर रहे हैं और चाहते हैं कि उसमें आपके काफी सारे पैसे खर्च ना हो तो इसके लिए आपको अपनी ट्रिप को प्लॉन करना चाहिए। आप जहां जा रहे हैं, इसके लोगों, संस्कृति, रीति-रिवाजों और भोजन आदि के बारे में थोड़ा-बहुत जानना आपको बहुत परेशानी से बचाएगा। इसके अलावा रिसर्च आपको उन महंगे शहरों के बारे में बताएगा जिनसे आप बचना चाहते हैं। रिसर्च के जरिए आप उस जगह की सस्ती जगहों व लोकल फूड के बारे में जान पाएंगे।

सोच-समझकर चुनें एयरलाइन

यदि आप अपनी यात्रा के लिए सही एयरलाइन नहीं चुनते हैं तो आपको फ्लाइंग पर अतिरिक्त पैसा खर्च करना पड़ सकता है।एक बजट एयरलाइन आपको कुछ पैसे बचा सकती है, इसलिए ट्रेवल के लिए आप सोच-समझकर एयरलाइन बुक करें। साथ ही अलग-अलग समय पर फ्लाइंग के चार्जेस अलग होते हैं, इसलिए उस पर भी फोकस जरूर करें।

ऑफ-सीजन में यात्रा करें

यह एक ऐसी ट्रिक है, जो ट्रेवल के दौरान आपके काफी सारे पैसे खर्च होने से बचा सकती है। पीक सीज़न के दौरान यात्रा करने से आपको अधिक पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, इसलिए पीक सीज़न की यात्रा से बचना समझदारी है। एयरलाइंस, होटल और फूड प्राइस आदि छुट्टियों के दौरान और क्रिसमस, ईस्टर, ईद और दिवाली जैसे अवसरों पर बढ़ जाती हैं। ऐसे में आप ऑफ सीजन में घूमने का प्लॉन करें। इससे आपके पैसे भी कम खर्च होंगे और भीड़ कम होने के कारण आप अच्छी तरह एंजॉय भी कर पाएंगे।

खाएं लोकल फूड

अगर आप बजट में घूमना चाहते हैं तो आपको अपने फूड पर भी फोकस करना चाहिए। ओवरप्राइज्ड कैफ़े और रेस्तरां में आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं जिन्हें आप स्थानीय स्थानों पर जाकर बचा सकते हैं जो ताजा भोजन परोसते हैं। इससे एक लाभ यह भी होगा कि आपको उस जगह के ऑथेंटिक फूड का स्वाद चखने का मौका मिलेगा।

हैप्पी हनीमून

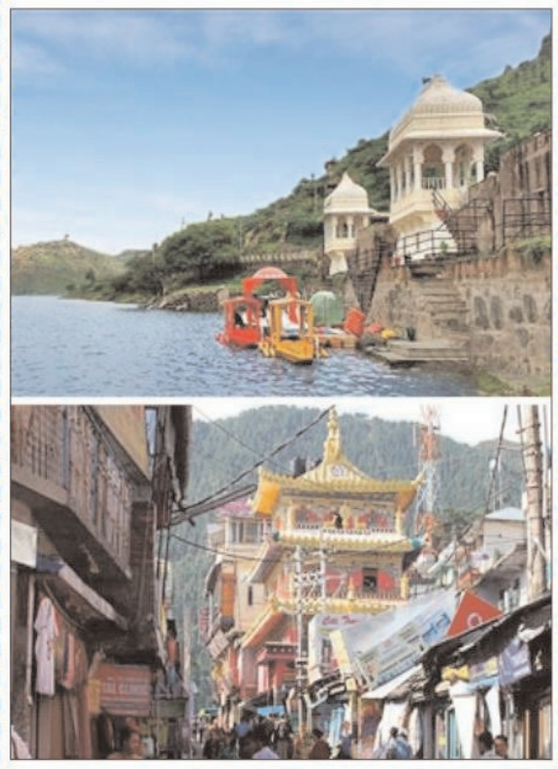

करना है पॉकेट फ्रेंडली हैप्पी हनीमून तो घूमें इन जगहों पर

शादी के बाद हनीमून किसी भी नवविवाहित जोड़े के लिए एक यादगार वक्त होता है। हनीमून ट्रिप को लेकर कपल्स के मन में कई तरह की एक्साइटमेंट होती है। लेकिन बहुत से कपल्स सिर्फ इसलिए हनीमून पर नहीं जा पाते, क्योंकि वह उनकी पॉकेट से बाहर होता है। हो सकता है कि आपकी भी जल्द शादी होने वाली है और आप कम बजट में हैप्पी हनीमून ट्रिप प्लॉन करना चाहते हैं तो ऐसे में आप इन जगहों पर जा सकते हैं-

हिमाचल प्रदेश

दिल्ली से 400 किलोमीटर की दूरी पर हिमाचल प्रदेश एक बेहद ही खूबसूरत जगह है, जहां पर आप कम बजट में अपने पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं। यह आध्यात्मिक गुरु, दलाई लामा का घर है और इसमें कई जगह हैं, जैसे कि भागसू फॉल्स, शिव कैफ़े आदि जगहों पर जा सकते हैं और ट्रेकिंग और अन्य एडवेंचर्स एक्टिविटीज कर सकते हैं। यहां पर आपको व्यक्ति प्रति दिन 300 रूपए में ठहरने की जगह मिल सकती है।

केरल

केरल एक बेहद ही खूबसूरत राज्य है और न्यू कपल्स के लिए इसे एक बेहतरीन घूमने की जगह माना जाता है। यहां की नेचुरल ब्यूटी हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। केरल को भगवान का अपना देश माना जाता है, जिस कारण हर व्यक्ति केरल के मंदिरों को देखना चाहता है। यहां बहुत सिद्ध मंदिर हैं। कुछ मंदिरों में पद्मनाभस्वामी मंदिर, गुरुवायुर मंदिर, वडक्कुन्नत मंदिर, अनंतपुरा झील मंदिर, थिरुमन्धाकुन्नु मंदिर, पडियानूर देवी मंदिर आदि प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह पद्मनाभस्वामी मंदिर है जो यहाँ बहुत प्रसिद्ध है।

उदयपुर

राजस्थान राज्य में कई बेहतरीन घूमने की जगहे हैं, लेकिन आप कम बजट में राजस्थान में हनीमून पर जाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको उदयपुर जाना चाहिए। यह अपेक्षाकृत काफी सस्ता है। आप यहां पर सिटी पैलेस से लेकर पिंचोला झील आदि कई खूबसूरत जगहों का लुत्फ उठा सकते हैं।

आगरा

आगरा के ताजमहल को दुनिया के सात अजूबों में शामिल किया गया है। यह बेमिसाल प्यार की निशानी है। ऐसे में आपके लिए आगरा से बेहतर घूमने की जगह कौन सी होगी। यहां घूमने में आपको 5000 रूपए से भी कम का खर्च आएगा। आगरा में आप ताजमहल के अलावा आगरा का किला, फतेहपुर सिकरी आदि घूम सकते हैं। वैसे अगर आप आगरा जा रहे हैं तो वहां का फेमस पेठा खाना ना भूलें।

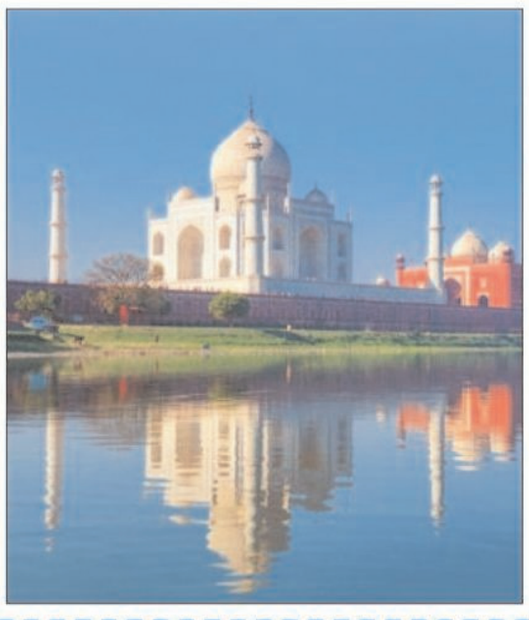

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

आप ने दिल्ली में फैलाई अराजकता : अश्विनी वैष्णव

नईदिल्ली। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आप और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से दिल्ली में अराजकता फैलाई है, उससे लोग प्रभावित हैं। उन्होंने (आप) झूठे वादे किए हैं। वह दिल्ली के लिए पानी की व्यवस्था नहीं कर सके और शराब पर ध्यान केंद्रित करते रहे। उन्होंने जिस तरह का घोटाला किया, उसमें कांग्रेस भी शामिल रही है। ईडी ने सभी तथ्यों के साथ चार्जशीट दायर की है और अदालत को सबूत दिए हैं। दिल्ली के लोगों को यह तय करने की जरूरत है कि क्या अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस और आप का ठगबंधन दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए उपयुक्त है। नई चार्जशीट दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के संबंध में दायर की गई है। इसके अलावा, आरोप पत्र में केजरीवाल को सरगना और मुख्य साजिशकर्ता के रूप में भी उल्लेख किया गया है। आरोप पत्र के अनुसार, वह गोवा चुनाव में रिश्वत के पैसे के इस्तेमाल से अवगत थे और इसमें शामिल थे।

आंध्र प्रदेश को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर कसा तंज

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने तंज कसते हुए लिखा कि मोदी सरकार अब बहुमत खोने के बाद शायद आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून 2014 पर तेजी से काम करेगी। जयराम रमेश का यह बयान उन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद सामने आया है, जिनमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की आंध्र प्रदेश में तेल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल हब बनाने की मांग मान ली है और इसके लिए केंद्र सरकार राज्य में 60 हजार करोड़ रुपये निवेश करेगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा आंध्र प्रदेश में एक तेल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल हब बनाने का वादा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून 2014 के तहत डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार में ही किया गया था।

हरियाणा में इनेलो-बीएसपी की बीच गठबंधन

चंडीगढ़। इनेलो महासचिव अभय सिंह चौटाला ने गुरुवार को कहा कि पार्टी आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव अपनी पूर्व सहयोगी मायावती की बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ेगी। बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद ने कहा कि चौटाला और मायावती ने 6 जुलाई को सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर विस्तृत चर्चा की थी। 90 विधानसभा सीटों में से बसपा 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी सीटों पर इनेलो अपने उम्मीदवार उतारेगी। हाल ही में मायावती के उत्तराधिकारी और पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में बहाल किए गए आनंद ने कहा कि अगर गठबंधन चुनाव जीतता है तो चौटाला को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बसपा ने 10 में से नौ संसदीय सीटों पर चुनाव लड़ा था जबकि इनेलो ने सात सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों अपना खाता खोलने में असफल रहे।

कर्नाटक के विकास पर भाजपा ने राज्य सरकार को घेरा

बेंगलूरू। कर्नाटक के विकास को लेकर भाजपा ने कांग्रेस को घेरा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने राज्य में सिद्धारामैया सरकार और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने बताया कि शिवकुमार रामनगर जिले का नाम बदलकर दक्षिण बंगलूरू रखने की बात कर रहे हैं। इस मुद्दे को उठाते हुए भाजपा नेता ने कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री को केवल रियल एस्टेट में दिलचस्पी है। मीडिया से बात करते हुए भाजपा नेता बीवाई विजयेंद्र ने कहा, वर्तमान कांग्रेस सरकार को राज्य के विकास की कोई परवाह नहीं है। राज्य में विकास कार्य ठप पड़े हैं। अब डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार रामनगर जिले का नाम बदलकर दक्षिण बंगलूरू करने की बात कर रहे हैं। भगवान जाने इस फैसले के पीछे क्या एजेंडा है? पूरे कर्नाटक को यह मालूम है कि शिवकुमार केवल रियल एस्टेट में दिलचस्पी रखते हैं। मुझे लगता है कि इस सोच पीछे भी एक रियल एस्टेट एजेंडा है।

सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई से अलग हुए जज

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दी क्योंकि न्यायाधीशों में से एक न्यायमूर्ति संजय कुमार ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। यह मामला 11 जुलाई को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, संजय करोल और संजय कुमार की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए रखा गया था। पीठ ने कहा कि एक अन्य पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति संजय कुमार सदस्य नहीं हैं, उत्पाद नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर मामलों में उनकी जमानत याचिकाओं को पुनर्जीवित करने के लिए मनीष सिसोदिया की दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। जैसे ही मामला सुनवाई के लिए आया, जस्टिस खन्ना ने कहा, हमारे भाई को कुछ कठिनाई है। वह निजी कारणों से इस मामले को सुनना पसंद नहीं करेंगे।

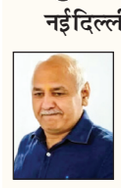

दिल्ली में इंडिया गठबंधन पूरी तरह से खत्म!

नईदिल्ली। लोकसभा चुनाव के कुछ हफ्ते बाद, राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) के बीच गठबंधन सुलझता दिख रहा है। दोनों दल विपक्षी इंडिया गुट के प्रमुख घटक हैं। चुनाव नतीजों में केंद्र में शासन करने वाली भाजपा को दिल्ली की सभी सात सीटें मिलीं। कांग्रेस ने तीन निर्वाचन क्षेत्रों- चांदनी चौक, उत्तर पश्चिम दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली- पर चुनाव लड़ा, जबकि आप ने अपने सीट-बंटवारे समझौते के तहत पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। भाजपा ने लगातार तीसरी बार दिल्ली में संसदीय चुनावों में जीत हासिल की।

कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि पार्टी के तीनों उम्मीदवारों - जेपी अग्रवाल (चांदनी चौक), उदित राज (उत्तर पश्चिम दिल्ली) और कन्हैया कुमार (उत्तर पूर्वी दिल्ली) ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) को बताते हुए अपनी हार के लिए आप को जिम्मेदार ठहराया है। दो सदस्यीय तथ्य-खोज समिति ने कहा कि उन्हें अपने अभियानों के दौरान कथित तौर पर आप से सहयोग की कमी का सामना करना पड़ा। ऐसे समीक्षा पैनल का गठन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन राज्यों के लिए किया है जहां लोकसभा चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक या उससे नीचे था।

दिल्ली पर एआईसीसी पैनल में पार्टी के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया और रजनी पाटिल शामिल हैं। पुनिया ने कहा, पैनल की रिपोर्ट अब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को सौंप दी गई है। जबकि कांग्रेस और आप दोनों राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने रहेंगे, दोनों दलों के नेताओं ने खुले तौर पर संकेत दिया है कि फरवरी 2025 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए उनके बीच कोई सीट-बंटवारा समझौता नहीं हो सकता है। कांग्रेस की दिल्ली इकाई के नेताओं समेत जिला पार्टी अध्यक्षों ने कहा कि पार्टी को भविष्य में आम आदमी पार्टी (आप) के साथ कोई गठबंधन नहीं करना चाहिए और आगामी विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ना चाहिए।

कांग्रेस, जो 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में दिल्ली में अपना खाता खोलने में विफल रही, अब आप की परेशानियों में एक अवसर को महसूस करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी में वापसी करना चाह रही है, जिसके शीर्ष नेतृत्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला मामले के सिलसिले में जहां मुख्यमंत्री केजरीवाल पिछले कुछ महीनों से जेल में हैं, वहीं उनके पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पिछले साल की शुरुआत से तिहाड़ जेल में बंद हैं। जाहिर तौर पर, कांग्रेस के पतन के कारण दिल्ली में आप का उदय हुआ, 2013 में सत्ता से बाहर होने के कुछ ही वर्षों में सबसे पुरानी पार्टी का वोट आधार आम आदमी पार्टी की ओर खिसक गया।

बजट पेश होने से पहले प्रधानमंत्री की अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक

■ वित्त मंत्री भी रहीं मौजूद

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई को पेश होने वाले केंद्रीय बजट से पहले अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की, इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहीं। विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों में सुरजीत भल्ला, ए के भट्टाचार्य, प्रोफेसर अशोक गुलाटी, गौरभ बल्लभ, अमिता बत्रा, महेंद्र देव और के वी कामथ शामिल थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में 2024-25 का बजट पेश करने वाली हैं। प्रधानमंत्री की बैठक में अर्थशास्त्रियों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों के अलावा नीति-आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और अन्य सदस्य भी शामिल हुए हैं।

यह मोदी 3.0 सरकार का पहला प्रमुख आर्थिक दस्तावेज होगा, जिसमें अन्य बातों के अलावा, 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप पेश करने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले महीने संसद की संयुक्त बैठक में अपने संबोधन में संकेत दिया था कि सरकार सुधारों की गति को तेज करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्यवादी दृष्टिकोण का एक प्रभावी दस्तावेज होगा।

इससे पहले, सीतारमण ने आगामी बजट पर अर्थशास्त्रियों और भारतीय उद्योग जगत के प्रमुखों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा की है। कई विशेषज्ञों ने सरकार से उपभोग को बढ़ावा देने के लिए आम आदमी को कर में राहत देने और मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने तथा आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है।

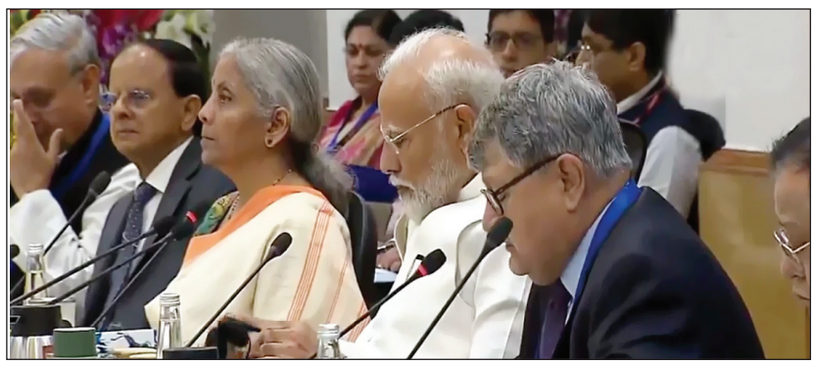

भारत को गिग श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय कानूनों की आवश्यकता: कांग्रेस

गिग श्रमिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपनी राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों का हवाला देते हुए, कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि भारत को ऐसे श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय कानूनी और सामाजिक सुरक्षा वास्तुकला की आवश्यकता है और उम्मीद है कि आगामी केंद्रीय बजट उस दिशा में एक कदम उठाएगा। कांग्रेस महासचिव, प्रभारी संचार, जयराम रमेश ने कहा कि कर्नाटक प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स बिल, 2024 एक ऐतिहासिक अधिकार-आधारित कानून है जो राज्य में प्लेटफ़ॉर्म-आधारित गिग श्रमिकों को औपचारिक अधिकार और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है।

कर्नाटक सरकार ने पिछले महीने प्रस्तावित कर्नाटक प्लेटफ़ॉर्म आधारित गिग वर्कर्स बिल, 2024 का एक मसौदा जारी किया था, जिसका उद्देश्य अन्य तंत्रों के बीच एक बोर्ड, कल्याण निधि और शिकायत सेल के निर्माण के साथ राज्य में उनके अधिकारों की रक्षा करना था। रमेश ने विधेयक की कुछ विशेषताओं को सूचीबद्ध किया जैसे कि गिग श्रमिकों की वकालत के लिए गिग श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण निधि और गिग श्रमिक कल्याण बोर्ड की स्थापना।

विधेयक में सरकार के साथ सभी गिग श्रमिकों के अनिवार्य पंजीकरण का भी आह्वान किया गया है और कहा गया है कि एग्रीगेटर्स अब 14 दिन की पूर्व सूचना और वैध कारण बताए बिना किसी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाल सकते हैं। बिल के मुताबिक, एग्रीगेटर्स को हर हफ्ते गिग वर्कर्स को भुगतान करना होगा। रमेश ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता, राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा के बाद से भारत के गिग श्रमिकों के लिए एक अग्रणी आवाज रहे हैं।

पीएम मणिपुर का दौरा कर शांति की अपील करें : राहुल

नयी दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को कहा कि ''मणिपुर की स्थिति में आज भी सुधार नहीं हुआ है और वह दो टुकड़ों में बंटा हुआ है'', ऐसे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को राज्य का दौरा कर लोगों की तकलीफ सुननी चाहिए और शांति की अपील करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' (इंडिया) के घटक दल मणिपुर में शांति की ज़रूरत को संसद में पूरी शक्ति के साथ उठाकर, सरकार पर इस त्रासदी को खत्म करने का दबाव बनाएंगे। राहुल गांधी ने गत सोमवार को मणिपुर का दौरा कर हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की थी।

उन्होंने अपने इस दौरे का एक वीडियो बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर साझा किया। उन्होंने कहा कि 22 जुलाई से आरंभ हो रहे संसद के मानसून सत्र में मणिपुर का मुद्दा उठाएंगे। उन्होंने वीडियो साझा करते हुए पोस्ट किया, ''मणिपुर में हिंसा शुरू होने के बाद, मैं तीसरी बार यहां आ चुका हूं, मगर अफसोस स्थिति में कोई सुधार नहीं है - आज भी प्रदेश दो टुकड़ों में बंटा हुआ है। घर जल रहे हैं, मासूम ज़िंदगियां खतरे में हैं और हज़ारों परिवार राहत शिविर में जीवन काटने पर मजबूर हैं।''

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को खुद मणिपुर आ कर प्रदेशवासियों की तकलीफ़ सुनने के साथ ही शांति की अपील करनी चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी कहा, ''कांग्रेस पार्टी और 'इंडिया' गठबंधन मणिपुर में शांति की ज़रूरत को संसद में पूरी शक्ति के साथ उठाकर, सरकार पर इस त्रासदी को खत्म करने का दबाव बनाएंगे।'' वीडियो के मुताबिक, जब राहल गांधी ने महिलाओं के एक समूह के समक्ष सवाल किया कि हिंसा क्यों शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि गहतफहमी के कारण शुरू हुई और हिंसा से किसी का फायदा नहीं है।

मनोज तिवारी ने केजरीवाल से सीएम पद से इस्तीफे की मांग की

नईदिल्ली। लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन पर दिल्ली शराब नीति घोटाले में केंद्रीय व्यक्ति होने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में, उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि स्लम क्षेत्र के विकास के लिए दिए गए धन को आप के नेतृत्व वाली सरकार ने शराब घोटाले में लगा दिया। तिवारी ने नैतिक आधार पर केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करते हुए दावा किया कि आप पार्टी ने जन कल्याण धन का दुरुपयोग किया है। तिवारी ने दावा किया, शराब घोटाले के लिए आप ने झुग्गी-झोपड़ी इलाकों के लिए आवंटित धन का दुरुपयोग किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि केजरीवाल ने पहले ही कसम खाई थी कि अगर उनके खिलाफ कोई आरोप साबित हुआ तो वह इस्तीफा दे देंगे। तिवारी ने कहा, ईडी की चार्जशीट में स्पष्ट सबूत सामने आने के बाद, हम उम्मीद करते हैं कि वह नैतिक आधार पर पद छोड़ देंगे। उन्होंने आगे कहा कि केजरीवाल को आरोपपत्र में 37वें आरोपी के रूप में नामित किया गया है।

खेल
प्रमुख समाचार

चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगा भारत

नईदिल्ली। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) को भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) झटका देगा। चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी-मार्च में हाइब्रिड मॉडल में आयोजित होने की संभावना है। इसकी बहुत कम संभावना है कि भारत वनडे मैच खेलने के लिए पाकिस्तान जाएगा। पाकिस्तान के पास चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी का अधिकार है। 2017 के बाद पहली बार क्रिकेट कैलेंडर में वापसी कर रहा है। हालांकि टूर्नामेंट के कुछ मैच संयुक्त अरब अमीरात या श्रीलंका में आयोजित होने की संभावना है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी।

दोनों टीमों ने पिछली बार 2012-13 में सीमित ओवरों की द्विपक्षीय सीरीज खेली थी, जब पाकिस्तान ने भारत का दौरा किया था लेकिन भारत ने 2007 के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी टेस्ट खेलने से इनकार कर दिया है, जब दोनों टीम भारतीय सरजमीं पर आपस में भिड़ी थीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले महीने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद को एक मसौदा कार्यक्रम सौंपा था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने कहा है कि अगर भारत अगले साल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम पाकिस्तान भेजेगा तो पीसीबी उसके साथ द्विपक्षीय सीरीज खेलने के तैयार है। नकवी से भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के हालिया साक्षात्कार के बारे में पूछा गया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्रशंसा की। दोनों पड़ोसी देशों का विदेश में टेस्ट सीरीज खेलना 'शानदार' होगा। नकवी ने कहा, ''देखिए, अगर इस संबंध में कोई विकल्प आता है तो हम उस पर विचार करेंगे, लेकिन अभी हमारा लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करना है और पहले भारत को टूर्नामेंट के लिए आने देना है।'' फिलहाल चैंपियन्स ट्रॉफी तक कोई समय उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हमारी टीम का यात्रा कार्यक्रम तय हो चुका है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को उतार-चढ़ाव भरे सत्र में मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। कंपनियों की पहली तिमाही के नतीजों की घोषणा से पहले निवेशकों ने दिग्गज शेयरों में मुनाफावसूली की। बाजार में कमजोरी का यह लगातार दूसरा दिन था। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 27.43 अंक या 0.03 प्रतिशत की गिरावट के साथ 79,897.34 पर बंद हुआ। शुरुआती कारोबार में सूचकांक 245.32 अंक चढ़कर 80,170.09 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, लेकिन बाद में हैवीवेट शेयरों में बिकवाली के कारण इसकी बढ़त कम हो गई। सेंसेक्स में आज 79,464.38 और 80,170.09 के रेंज में कारोबार हुआ। वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी 8.50 अंक या 0.03 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,315.95 पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में यह 24,402.65 के उच्चतम और 24,193.75 के निचले स्तर के बीच घूमता रहा।

बजट: पीएसयू के लिए रियायतें ब्रोकरेज की बड़ी उम्मीदें

नईदिल्ली। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई 2024 को बजट पेश करने जा रही हैं। पूर्ण बजट के इंतजार के पल जहां एक तरफ नजदीक आते जा रहे हैं तो साथ ही साथ, आम लोगों से लेकर ब्रोकरेज फर्मों तक की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। अगले 15 दिन भारतीय शेयर बाजारों के लिए अहम होने वाला है, क्योंकि जो भी बजट आता है उस हिसाब से मार्केट को अपनी दिशा-दशा तय करनी होगी। एनालिस्ट्स के अनुसार, जून तिमाही के कॉर्पोरेट अर्निंग सीजन में स्टॉक संबंधी हलचल देखने को मिल सकती हैं और असर ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट पर पड़ सकता है। मॉर्गन स्टेनली के एनालिस्ट ने एक नोट में लिखा है कि उम्मीदें (बजट से पहले इक्विटी मार्केट परफॉर्मेंस से मापी गई) यह निर्धारित करने में अहम हैं कि बजट के तुरंत बाद बाजार क्या करता है। बजट के बाद 30 दिनों में बाजार दो में से तीन अवसरों पर गिरता है।

टॉप 8 शहरों में अप्रैल-जून में मकानों की बिक्री में 6% गिरावट

नईदिल्ली। देश के शीर्ष आठ शहरों में मकानों की बिक्री में अप्रैल-जून में पिछली तिमाही की तुलना में छह प्रतिशत की गिरावट आई है। आवासीय ब्रोकरेज फर्म प्रॉपटाइगर ने बृहस्पतिवार को आवासीय मांग और आपूर्ति के तिमाही आंकड़े जारी किए। प्रॉपटाइगर आरईए इंडिया का हिस्सा है। आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-जून की अवधि में आवासीय बिक्री छह प्रतिशत घटकर 1,13,768 इकाई रह गई, जबकि इससे पहले जनवरी-मार्च तिमाही में यह 120,642 इकाई थी। हालांकि, अप्रैल-जून में आवासीय बिक्री 42 प्रतिशत बढ़ी, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में 80,245 इकाईयां बिकी थीं। आरईए इंडिया के समूह समूह मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) विकास वधावन ने कहा, आम चुनाव के कारण अप्रैल-जून में मकानों की मांग में कमी आई, हालांकि मजबूत बुनियादी बातों के कारण रियल एस्टेट निवेश के प्रति उपभोक्ता भावना बेहद सकारात्मक बनी हुई है।

शॉपिंग मॉल्स के लिए रिटेल स्पेस की मांग में उछाल

नईदिल्ली। देश के आठ प्रमुख शहरों में खुदरा विक्रेताओं की बेहतर मांग के दम पर अप्रैल-जून में शॉपिंग मॉल के लिए खुदरा स्थानों की मांग सालाना आधार पर 15 प्रतिशत बढ़कर 6.12 लाख वर्ग फुट हो गई। रियल एस्टेट सलाहकार कुशमैन एंड वेकफील्ड इंडिया की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, इन आठ प्रमुख शहरों में प्रमुख इलाकों में खुदरा स्थान की मांग कैलेंडर वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर चार प्रतिशत बढ़कर करीब 14 लाख वर्ग फुट हो गई है। आंकड़ों के अनुसार, शॉपिंग मॉल के लिए स्थान की मांग अप्रैल-जून 2024 में बढ़कर 6,12,396 वर्ग फुट हो गई, जो एक साल पहले समान अवधि में 5,33,078 वर्ग फुट थी। समीक्षाधीन अवधि में प्रमुख इलाकों में मांग चार प्रतिशत बढ़कर 13,89,768 वर्ग फुट हो गई। पिछले साल समान अवधि में यह 13,31,705 वर्ग फुट थी।

नयी सरकार के पहले बजट से उम्मीदें

डॉ. पीएस

सभी की निगाहें तीसरी मोदी सरकार द्वारा लाये जा रहे केंद्रीय बजट पर है। ऐसे कयास लगाये जा रहे हैं कि क्या आगामी बजट में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की एकतरफा छाप दिखेगी या गठबंधन की राजनीति का दबाव भी होगा। कयासों का रुख ज्यादातर इस तरफ है कि सरकार निश्चित तौर पर बजट के माध्यम से भारत के आर्थिक विकास को उसी पथ पर और तेजी से बढ़ाने की कोशिश करेगी, जो उसने पिछले दस वर्षों में स्थापित किया है। बजट के माध्यम से सरकारें वित्तीय वर्ष के दौरान देश के आर्थिक विकास को विभिन्न आंकड़ों के माध्यम से प्रस्तावित करने की कोशिश करती हैं।

इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है क्योंकि बजट एक रोडमैप है, जिसके अनुसार सरकार अर्थव्यवस्था को संचालित करती है। दो-तीन दशकों से भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़े बुनियादी बदलाव हुए हैं और आज वैश्विक स्तर पर भारत की मजबूत छवि है। वैश्वीकरण के इस युग में भारत के लिए अटूट आर्थिक संभावनाएं इसलिए भी लगातार बनी हुई है क्योंकि भारत विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है। हालांकि घरेलू मोर्चे पर इस कारण बेरोजगारी की एक अनवरत समस्या भी है, फिर भी लगातार बढ़ती आर्थिक विकास दर विश्व को आकर्षित करने में सक्षम बनी हुई है।

इस बात का श्रेय मोदी सरकार को जाता है कि उसके नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था जीडीपी के पैमाने पर तेज प्रगति करते हुए वैश्विक दौड़ में पांचवें पायदान पर पहुंची है। विश्व के सभी बड़े आर्थिक संस्थान व रेटिंग एजेंसियां आने वाले कुछ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था को सात ट्रिलियन डॉलर के मुकाम पर पहुंचते हुए देख रही हैं। तब जापान और जर्मनी भारत से पीछे रह जायेंगे। अगर मोदी सरकार के पिछले दो कार्यकाल की आर्थिक नीतियों का विश्लेषण करें, तो हम पाते हैं कि सरकार का रुख पूंजीगत खर्चों पर बहुत अधिक एकाग्र और सकारात्मक है। आंकड़ों के हिसाब से मनमोहन सिंह सरकार अपने आखिरी दौर में पूंजीगत खर्चों पर बजट का करीब 12 प्रतिशत खर्च कर रही थी, जिसे मोदी सरकार बड़ी तेजी से बढ़ाते हुए 22 प्रतिशत से अधिक कर चुकी है। वित्त वर्ष 2023-24 में आधारभूत सुविधाओं पर हुआ वास्तविक खर्च 18.6 प्रतिशत है और बाकी बचा 3.6 प्रतिशत हिस्सा विभिन्न राज्यों, सार्वजनिक उपक्रमों को वित्तीय ऋण के तौर पर आवंटित किया गया है। इस खर्च के चलते ही अर्थव्यवस्था में तेजी आयी और निजी निवेश का प्रतिशत भी लगातार बढ़ा। इससे जीडीपी की लगातार वृद्धि होती रही है।

यह भी एक हकीकत है कि भारत में युवाओं में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। रोजगार में बढ़ोतरी हो रही है, पर अवसरों की संख्या उतनी नहीं हो पा रही है कि इस समस्या का ठीक से समाधान हो सके। मोदी सरकार को इस बार आम चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिलने का यह एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। बजट में इस संदर्भ में प्रावधान होने चाहिए। यह स्थिति भी चिंताजनक है कि निजी क्षेत्र निवेश के बदले सरकार से बहुत अधिक अपेक्षाएं रखता है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था नब्बे के दशक के उस दौर में नहीं है, जब निजी क्षेत्र की मनमानी बहुत अपेक्षित थी। फिर भी पिछले कई बजट में यह देखा जा सकता है कि सरकारें निजी क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहती हैं। इसके चलते सरकार का पूर्ण ध्यान ग्रामीण अर्थव्यवस्था, छोटे उपभोक्ता, आम आदमी की बचत, बैंकिंग निवेश पर अधिक ब्याज दर और दिन-प्रतिदिन के उपभोग में आने वाली वस्तुओं के मूल्य में बढ़ोतरी जैसे मसलों पर समुचित रूप में नहीं जा पाता। यह भी बड़ी अजीब बात है कि आंकड़ों के माध्यम से इस बात को समझाने की कोशिश होती है कि आयकर की दरों में कमी या आयकर की सीमा में बदलाव देश के मात्र एक या दो प्रतिशत लोगों को ही प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करता है। कई विश्लेषक कहते हैं कि आयकर दरों में बदलाव से समाज के निचले तबके को फायदा नहीं होता है तथा सरकार के राजस्व में भी कमी आ जाती है। आम उपभोग में आने वाली वस्तुओं पर अमूमन 12 और 18 प्रतिशत जीएसटी है, जो आम जन की जेब पर आर्थिक बोझ डालती है।

मुख्यमंत्री ने 'एक पेड़ मां के नाम' महा वृक्षारोपण अभियान-2024 का किया शुभारंभ

प्रदेशव्यापी अभियान के तहत 33 जिलों में होगा 4 करोड़ वृक्षों का रोपण
एक पेड़ मां के नाम लगाने मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से किया आह्वान

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर के अटल नगर स्थित जैव विविधता पार्क में 'एक पेड़ मां के नाम' महावृक्षारोपण अभियान-2024 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री साय ने पूर्ण विधि विधान से पूजन कर पीपल के पौधे का रोपण कर महावृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री द्वारा अभियान का बैनर जारी किया गया। इस अभियान के तहत वन विभाग द्वारा प्रदेशभर में 4 करोड़ वृक्ष लगाये जाएंगे। इसी के अंतर्गत में आज प्रदेश के 33 जिलों में कुल 4 लाख पेड़ लगाए गए। आज महावृक्षारोपण अभियान के शुभारंभ के मौके पर जैव विविधता पार्क में मुख्यमंत्री साय के साथ सभी कैबिनेट मंत्रीगणों, स्कूली बच्चों, सीआरपीएफ के जवानों, पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों ने 20 हजार पेड़ लगाए। मुख्यमंत्री साय ने ओपन जिप्सी में वृक्षारोपण क्षेत्र का भ्रमण कर अभियान में हिस्सा ले रहे लोगों का उत्साह वर्धन किया। वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि उप मुख्यमंत्री द्वय अरूण साव एवं विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, खेल मंत्री श्री टंकराम वर्मा, विधायक श्री इंद्र कुमार साहू एवं श्री गुरु खुशवंत साहेब उपस्थित थे। सभी ने एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 140 करोड़ लोगों से आह्वान किया है कि सभी अपनी मां के नाम से एक पेड़ लगाएं। उनके आह्वान पर यह एक आंदोलन बन गया है, हम लोग छत्तीसगढ़ में भी इसको अभियान के रूप में ले रहे हैं और अकेले वन विभाग का 4 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के 33 जिलों में वन विभाग द्वारा 6 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। बहुत सी प्रजातियों के पेड़ लगाएं जा रहे हैं। पीपल का पेड़ जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, नीम का पेड़, हर्रा बहेड़ा आंवला जैसे गुणकारी पौधे लगाए जा रहे हैं हर किसी को पेड़ लगाना बहुत आवश्यक है आप सब लोग देख रहे हैं कि पेड़ कम होने से गर्मी के दिनों में गर्मी बहुत बढ़ रही है इस साल तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पूरे देश में पड़ी है। पारा 50 डिग्री पहुंच गया। पूरे विश्व में गर्मी से मरने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है, ऐसे समय में बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम सभी पेड़ लगाएं। आज वृक्षारोपण अभियान में हमारे स्कूली बच्चे शामिल हुए, हमारे सीआरपीएफ के जवान शामिल हुए, हमारे वन और पुलिस विभाग का अमला भी शामिल हुआ।

कांग्रेस पार्टी ने 21 बिंदु-वार सुझाव केन्द्रीय वित आयोग को लिखित में प्रतिवेदन के रूप में दिया

रायपुर। जीएसटी काम्पासेंशन, विशेष राज्य, कुपोषण के लिये राहत पैकेज कृषि क्षेत्र के लिये विशेष पैकेज, अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति की स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिये बेहतरी के लिये विशेष पैकेज, नये उद्योग स्थापित करने के लिये विशेष पैकेज, नवा रायपुर में आईटी हब एवं होल सेल कारीडोर व ऐरो सिटी के लिये विशेष पैकेज की मांग प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने रखी

रायपुर 11 जुलाई 2024। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग और वित्तीय संसाधनों में राज्य की हिस्सेदारी बढाने की मांग की।

आदिवासियों की 30 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की 12 प्रतिशत से अधिक और अन्य पिछडा वर्ग की बडी आबादी, आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी चुनौतियां, चूंकि नक्सली स्थिति को दुर्लभ आंतरिक क्षेत्रों में व्यापक बुनियादी ढांचे के विकास से दूर किया जा सकता है, इसलिए विभिन्न बुनियादी सुविधाओं के तेजी से विकास के लिए एक विशेष पैकेज प्रदान किया जाना चाहिए।माओवाद रोजगार की जरूरत, विमान सेवाओं का रायपुर के साथ साथ बिलासपुर बस्तर सरगुजा तक विस्तार, छत्तीसगढ में आई टी हब की स्थापना हेतु मदद की जरूरत छत्तीसगढ में जलवायु के कारणों से कृषि लागत ज्यादा है और उत्पादन कम अत: किसानों को प्रोत्साहन सहायता मिलना चाहिए, सौर उर्जा को बढ़ावा देने के लिये जन-जनत क पहुंचाने के लिये विशेष राहत पैकेज की मांग की, वुमेन एवं चाईल्ड के लिये हेल्थ फेसलिटी के लिये नये अस्पताल स्थापित करने के लिये विशेष राहत पैकेज की मांग की, खेल को बढ़ावा देने के लिये हर ब्लाक स्तर नये मैदान तैयार करने के लिये राहत पैकेज की मांग की, सिकलसेल के लिये शोध और पीड़ित परिवारों को सहायता की आवश्यकता, इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिये विशेष सहायता की आवश्यकता है।

सरकार धान बीज की उपलब्धता के लिये गंभीर नहीं हैः दीपक

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि खरीफ का सीजन आ चुका है, किसान बोने की तैयारी करके मानसून का इंतजार कर रहा है, लेकिन किसान विरोधी साय सरकार छत्तीसगढ़ के 80 प्रतिशत सोसायटीयों में खाद और बीज आवश्यक मात्रा में अब तक नही पहुंचा पाई है। किसान खाद बीज के लिये सोसायटियों के चक्कर काटने को मजबूर है। सरकार की तरफ से खाद बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये अभी तक कोई ठोस प्रयास शुरू नहीं किया गया है। किसानों के लिये उर्वरक की उपयोगिता उसके समय पर मिलने पर ही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की अकर्मण्यता और संवेदनहीनता के चलते छत्तीसगढ़ के किसान खाद और बीच के लिए भटक रहे हैं। खरीफ सीजन 2024-25 के लिए जो खाद और बीज डबल लॉक के गोदामों में रखे गए हैं, वहां से सिंगल लॉक की सोसाइटियों तक पहुंचाने के लिए परिवहन की व्यवस्था नहीं है। छत्तीसगढ़ के लगभग 80 प्रतिशत सोसाइटीयों में खाद और बीज के पर्याप्त स्टॉक नहीं है। अनेकों स्थानों पर पूर्व के परिवहन ठेकेदारों से किए गए निविदा को खत्म कर दिया गया है, लेकिन भारी भरकम कमिशन मांगे जाने के चलते नए परिवहनकर्ता रूचि नहीं दिखा रहे हैं, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि अभी खरीफ सीजन की शुरूआत ठीक से हुआ नहीं है। पूरे राज्य में अमानक खाद बीज का भंडारण शुरू हो गया है। विगत दिनों बस्तर के पखांजूर में नकली खाद से भरा ट्रक पकड़ा गया, सूचना के मुताबिक नकली खाद राजस्थान से मंगाया गया था, किसानों का आरोप है कि भाजपा शासित प्रदेशों से नकली खाद छत्तीसगढ में खपाए जा रहे हैं। हाल ही में बेमेतरा जिले के नवागढ़ तहसील के सरकारी सोसायटी में अमानक नैनो यूरिया का मामला सामने आया था। भाजपा की सरकार में छत्तीसगढ़ नकली खाद, अमानक बीज, नकली दवा, घटिया कीटनाशक और एक्सपायरी नैनो यूरिया खपाने का अड्डा बन गया है। कमीशनखोरी के लालच में भाजपाई किसान विरोधी षड्यंत्र रच रहे हैं।

बाबू भैया की कलम से ✍

जो है वो तो हइये है, सिर्फ सरकार बदली

वही कानून व्यवस्था,वही रेत माफिया,वही कोल माफिया,वही राइस मिल माफिया ,वही महादेव एप, वही शराब का धंधा,(अहाता प्लस में), वही का वही ,जैसा का वैसा चलता हुआ सिस्टम। कुछ तो नहीं बदला, बस बदली है तो सरकार। तब कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार गद्दी पर बिराजमान थी। अब विष्णुदेव साय की भाजपा सरकार गद्दी पर बैठी है। कद काठी व कर्म प्रभाव के साथ मंत्रीगणों में विभागों का बटवारा। नए लोगों को भारी भरकम विभाग , और पुराने चेहरों को सम्मानजनक विभाग बांट दिए गए।काबिल व्यक्तित्व के धनी विजय शर्मा को प्रदेश की कानून व्यवस्था की नब्ज पकड़ा दी गई। पहली बार विधायक पद पाया। गृह विभाग जैसा वजनी व तनाव देने वाले विभाग की जिम्मेदारी मिली। सर पर ओले पड़े वाली कहावत चरितार्थ होने लगी। रोज हिंसा करने वाले ,पूरे देश की व्यवस्था को ना मानने वाले नक्सलियों को ललकारने की जगह पुचकारने का काम कर बैठे। कह दिया हम जहां कहो बात करने तैयार हैं। मुख्य धारा में आ जावो। इधर बात करने की पेशकश की उधर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों का मुठभेड़ में व्यापक संहार करना शुरू किया। बात चर्चा के स्थान पर टकराव पर आकर टिक गई। अनेकों नक्सली मारे गए। आपसी चर्चा की जगह मुक़ाबले की बात शुरू हो गई। मुकाबले का सिलसिला बरसात में भी जारी है। पूरा मुकाबला नक्सलियों पर केंद्रित सा हो गया। इधर प्रदेश में रोज चाकूबाजी,अनैतिक कर्म,शराब खोरी,महिलाओं से चैन स्नेचिंग,मारपीट,लूट,घरेलू हिंसा और हत्याओं की घटनाओं के साथ, अनेक घटनाओं को असामाजिक तत्व बेखौफ अंजाम दे रहे हैं। वह भी खास कर जहां सरकार का ठिकाना(राजधानी) है। राजधानी कांप रही है,महिलाएं खौफ में हैं,कोई बाहर जाए तो घर के लोग उसके वापस आते तक अनचाही आशंका से पीड़ित रहते हैं। तब ताम्रध्वज साहू थे तो भी यही हाल था। अब भी वही हाल है। तब यही चैन स्नेचिंग, हत्याएं,मारपीट,घरेलू हिंसा,आये दिन चाकूबाजी,लूट,महिलाओं से छेड़खानी, अनैतिक कर्म के मामलों की खबरों से अखबार अटें पड़े रहते थे। आज भी वही हाल है। अखबार उठाओं तो सबसे बड़ी खबर इसी तरह की घटनाओं से बनी दिखती थी। तब और अब में कुछ अंतर अगर दिखाई देता है तो यह कि तब नक्सल मुठभेड़ की खबरें कभी कभार ही आती थी। नक्सल वारदत भी कम दिखाई पड़ रही थी। अब बहुत बढ़ रही हैं। वहीं यह भी की मुठभेड़ में रिकॉर्ड संख्या में नक्सल मारे भी जा रहे हैं। लोगों का कहना है ,तब सरकार हमलावर नहीं थी। अब हमलावर भी हैं। एक तरफ बातचीत की पेशकश,दूसरी तरफ हमला भी चल रहा है। कहा भी जाता है की एक्शन का ही रिएक्शन होता है।

इधर निचले स्तर पर हो या ऊंचे, भ्रष्टाचार अपने स्तर पर तब भी कायम था, अब भी कायम है। इसका सबूत भले ही नहीं दिया जा सके पर जो इस भ्रष्टाचार को स्वयं भोग रहे हैं।सभी स्तर पर दैनंदिनी अहसास कर रहे हैं। उन्हें तो सरकार बदलने का अहसास भी इस मामले में नहीं हो पा रहा है। जो चल रहा था वही अब भी चल रहा है। किसी भी स्तर पर कुछ भी बदला नहीं जा सका है। तब की सरकार पर भाजपा हमलावर हुआ करती थी यहाँ तक कि भ्रष्टाचार के आरोपों का ऐसा नैरेटिव गढा गया कि, कांग्रेस की मजबूत दिख रही सरकार ही जाती रही।वर्तमान सरकार की वही आलोचना ,आरोप प्रत्त्यारोप ,उन्हीं शब्दों के साथ, कांग्रेस कर रही हैं। आज की हो या तब की सरकार इस विषय पर कुछ करना भी चाहे तो कुछ कर नहीं पाई। ईडी -आयकर-सीबीआई ने प्रदेश में बहुत कुछ किया। बड़े बडे चेहरों को जेल की दीवार के पार पहुंचा दिया। क्या इतने भर से शराब बिक्री में घपला,कोयला में कमीशन,लेव्ही चावल में कमीशन,रेत माफियाओं से सांठगांठ बंद हो गया। क्या राम राज्य आ गया। सब तरफ सब ठीक ठाक हो गया। आज भी सब चल रहा है बस कहीं कहीं पर चेहरे बदल रहे हैं। सरकार बदली है सिस्टम तो वही का वही है। उसका काम करने की राह भी वही है, घुड़सवार भर तो बदला है, घोड़ा तो वही है और उसी चाल से चल रहा है। जिस चाल में चलने की आदत उसे है। घुड़सवार कितना ही रास खींच ले उसे फर्क पड़ने वाला नहीं है। सिस्टम समय की नजाकत देख कर अपनी चाल धीमी जरूर कर लेता है, पर अपना तय रास्ता नहीं छोड़ता। उन्नीस-बीस का फर्क भर दिखाई पड़ जाय तो, सिस्टम की मेहरबानी। लंबा समय गुजर गया प्रजातंत्र को अपनाए हुए। कितने सपनों के साथ लोग सत्ता में आते देखे। अपवाद छोड़ सभी को कमोबेश सिस्टम में ढलते ही देखा है। लड़ते हुए अपवाद ही देखा है। जो थोड़ा बहुत लड़ने का प्रयास करते भी हैं। उन्हें मुख्य धारा के किनारे बैठने मजबूर कर दिया जाता है। ये अजीबो गरीब मजबूरी आज देश-प्रदेश के राजनीतिज्ञों में लड़ने की क्षमता को घटा रही है और बहती गंगा में हाथ....., के लिए मजबूर बना रही है। सिस्टम से मुकाबला ,नक्सल समस्या,भ्रष्टाचार, हो या माफियाओं से मुकाबला जैसी समस्यायों का निदान एक संस्था के बस की बात नहीं। यह सबके सामूहिक प्रयास से संभव हो सकने की आशा की जा सकती है। सिर्फ सरकार बदलने पर आरोप प्रत्त्यारोपों से यह नहीं हो पायेगा। अगर वास्तव में समाधान खोजना है तो किसी की गिरेबान में हाथ डालने के पहले अपने अपने गिरेबान में पहले झांक कर देखना होगा। वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। तो ही कुछ सही समझ में आएगा और तभी कुछ उम्मीद की जा सकती है। अन्यथा जो है वो तो हइये है। यही कहा जाएगा कि होइ है वही जो राम .....

छत्तीसगढ़/राजधानी — प्रमुख समाचार

आय जाति प्रमाण पत्र के लिए भटक रहे हैं छात्र

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने भाजपा सरकार पर असंवेदनशील होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य सरकार का राजस्व पखवाड़ा सिर्फ राजनीतिक इवेंट बनकर रह गया है। पटवारी, तहसीलदार, हड़ताल पर हैं, ऐसे में राजस्व पखवड़ा का औचित्य क्या है? नया शिक्षण सत्र शुरू हो चुका है, स्कूलों में प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है, एक तरफ सरकार राजस्व पखवाड़ा आयोजित कर जनता की समस्याओं को हल करने का झूठा दावा कर रही है, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में तहसीलदार हड़ताल पर हैं, राजस्व की रीढ़ माने जाने वाला पटवारी अमला पूरे प्रदेश में आंदोलित है। प्रदेश भर के छात्र आय, जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भटक रहे हैं। विद्यार्थी और उनके पालक परेशान हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि पटवारी की ज्यादातर मांगे, आम जनता को हो रही परेशानियों को लेकर है। संशोधन और त्रुटि सुधार के अधिकार के लिए है। तहसीलदार संघ की मांग भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में बढ़ते अपराध के खिलाफ है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से दबंगई बढ़ गई है।

मुख्य सचिव ने कलेक्टरों की बैठक ली

रायपुर। मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन और उपाध्यक्ष, राज्य नीति आयोग अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों की महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 डाक्यूमेंट पर सभी संभागों, जिलों से सुझावों लिए गए। छत्तीसगढ़ के विकास और भविष्य की योजनाओं पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया। जिला स्तर पर विशिष्ट समस्याओं, आवश्यकताओं और क्षमताओं पर जिला कलेक्टरों से प्राप्त सुझावों पर गहन चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं, क्षमताओं को पहचानें और उन्हें विजन डाक्यूमेंट में शामिल करने जरूरी कार्यवाही करें। उन्होंने विजन डाक्यूमेंट के संबंध में जिलों के जनप्रतिनिधियों, नागरिकों और विद्यार्थियों के सुझाव प्राथमिकता से लिए जाए। जिससे विजन 2047 दस्तावेज वास्तव में समावेशी और हर क्षेत्र की वास्तविक जरूरतों को पूरा कर सके। आगामी दिनों में विजन डाक्यूमेंट 2047 के संबंध में आयोजित संवाद कार्यक्रम में लोगों की जनसहभागिता सुनिश्चित की जाए।

अब मितानिनों को होगा ऑनलाईन प्रोत्साहन राशि का भुगतान

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 12 जुलाई को रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में राज्य की मितानिनों को ऑनलाईन प्रोत्साहन राशि दिए जाने की व्यवस्था का शुभारंभ करने के साथ ही सीधे उनके बैंक खातों में प्रोत्साहन राशि अंतरित करेंगे। राज्य स्तर से मितानिनों को ऑनलाईन प्रोत्साहन राशि का भुगतान पारदर्शी प्रशासन की ओर छत्तीसगढ़ सरकार का एक और कदम है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मुख्य आतिथ्य में ऑनलाईन प्रोत्साहन राशि का यह कार्यक्रम 12 जुलाई पूर्वान्ह 11 बजे से रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में होगा। उप मुख्यमंत्री द्वय अरूण साव तथा विजय शर्मा कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि होंगे। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल करेंगे। कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक सर्वश्री राजेश मूणत, पुरन्दर मिश्रा, अनुज शर्मा, मोतीलाल साहू, गुरू खुशवंत साहेब और इंद्र कुमार विशेष रूप से उपस्थित होंगे।

वित्त मंत्री चौधरी के वायरल वीडियो से भाजपा का रोजगार विरोधी उजागर

रायपुर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के वायरल वीडियो पर तंज कसते हुये प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि नौकरी दे नहीं सकते तो वादा क्यों करते हो? वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने मिलने आए युवाओं से कहा कि सरकारी नौकरी नहीं है जबकि प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में पद रिक्त है। भाजपा सरकार को प्रदेश के सरकारी विभागों में रिक्त पदों की संख्या सार्वजनिक करनी चाहिए और एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए ताकि युवाओं के बीच सच्चाई सामने आए और जल्द भर्ती की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी के नाम से एक लाख सरकारी पदों पर भर्ती का वादा किया था। अब भाजपा की सरकार युवाओं के वादों को पूरा करने में असमर्थ नजर आ रही है भाजपा सरकार के नियत में खोट है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। सच्चाई यह है सरकारी पद तो रिक्त हैं, लेकिन यह सरकार नौकरी देने के लायक नहीं है। एक बार फिर युवाओं के साथ धोखा भाजपा कर रही है।

एसआईटी की जांच तेज, आरोपी को घटना स्थल ले जाकर कर रही पूछताछ

बलौदाबाजार। बलौदाबाजार पुलिस की एसआईटी टीम 10 जून को ग्राम महकोनी स्थित अमर गुफा में जैतखाम काटे जाने और उसके बाद बलौदाबाजार में हुए प्रदर्शन, हिंसा, लूटपाट व आगजनी मामले को लेकर लगातार कार्यवाही कर रही है. पुलिस की एसआईटी टीम आज भीम आर्मी के बलौदाबाजार के किशोर नवरंगे को दशहरा मैदान प्रदर्शन स्थल लेकर पहुंची और विस्तार पूर्वक पूछताछ कर प्रदर्शन स्थल का जायजा लिया और आरोपी से पूछताछ की. राज्य शासन ने पूरे घटना के निष्पक्ष जांच के निर्देश दिया है, जिसके बाद एसपी विजय अग्रवाल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह के नेतृत्व में एसआईटी टीम जांच में लगी हुई है. पुलिस मामले में अब तक 159 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है. वही गिरफ्तार आरोपियों को रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है.

विश्वविद्यालय की विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया

कृषि विवि में नये शैक्षणिक सत्र से लागू होगी नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जुलाई-अगस्त से प्रारंभ नये शैक्षणिक सत्र में नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न प्रावधानों को लागू किया जाएगा। इन प्रावधानों के तहत स्नातक पाठ्यक्रमों में चार वर्ष की पढ़ाई पूर्ण न कर पाने वाले विद्यार्थियों को बीच में पढ़ाई छोड़ने पर सर्टिफिकेट तथा डिप्लोमा प्रदान किये जाएंगे। इसके साथ ही नवीन शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुरूप अब सैद्धान्तिक पढ़ाई की बजाय प्रायोगिक पढ़ाई पर अधिक ध्यान दिया जाएगा और इसे रोजगारमूलक बनाया जाएगा। इसके साथ ही विद्यार्थी ऑनलाईन

प्लेटफॉम के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकेंगे। पढ़ाई की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए नियमित अध्यापकों के अलावा विजिटिंग प्रोफेसर, प्रोफसर ऑफ प्रैक्टिस तथा एडजंट फैकल्टी की नियुक्ति भी की जाएगी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल की अध्यक्षता में आयोजित विद्या परिषद की बैठक में इस आशय के निर्णय लिये गये। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर की विद्या परिषद की बैठक दिनांक 09 जुलाई 2024 को आयोजित की गई। जिसमें स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को इसी शैक्षणिक सत्र (2024-25) से लागू किये जाने के प्रस्ताव को पारित किया गया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के तहत संचालित स्नातनक स्तर के पाठ्यक्रम जिसमें बी.एस.सी. (आनर्स) कृषि, बी.टेक. कृषि अभियांत्रिकी एवं बी.टेक. खाद्य प्रौद्योगिकी में इसे लागू किया जावेगा। इस नीति के लागू होने के उपरान्त स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थी प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में यदि पाठ्यक्रम स्तर की पढ़ाई छोड़ना चाहे तो उन्हें इसकी अनुमति होगी और इसके साथ उन्हें 10 सप्ताह का इंटर्नशिप कोर्स करने के साथ प्रथम वर्ष के उपरान्त प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) प्रदान किया जायेगा। यदि वह द्वितीय वर्ष के बाद पाठ्यक्रम की पढ़ाई से बाहर होता है तो इसी अवधि की इंटर्नशिप करने पर डिप्लोमा प्रदान किया जायेगा। ऐसे विद्यार्थी इस तहर के सर्टिफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर स्व-रोजगार या रोजगार का कार्य कर सकते हैं। अगर उन्हें स्व-रोजगार या रोजगार में कुछ दिन कार्य करने के उपरान्त असंतुष्टि मिलती है और वह आगे की पढ़ाई जारी करना चाहते हैं।

माध्यमिक शिक्षा मण्डल के नवनियुक्त सदस्यों का हुआ स्वागत सम्मान

रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर के सभागार में आज यहां नवनियुक्त मण्डल सदस्यों का स्वागत एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं माँ सरस्वती की प्रतिमा में माल्यार्पण कर किया गया। समारोह में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के नवनियुक्त सदस्य डोमन लाल कोर्सेवाड़ा विधायक अहिवारा, मोतीलाल साहू विधायक रायपुर ग्रामीण, रामकुमार टोप्पो विधायक सीतापुर एवं श्री आशाराम नेताम विधायक कांकेर तथा शिक्षाविद् एल.डी. दुबे, ओंकार सिंह ठाकुर,

ऋषि कश्यप, जितेन्द्र सिंह ठाकुर, प्रफुल्ल शर्मा, सुनील पंड्या, चन्द्रकांत तिवारी, डॉ. हितेश कुमार दीवान, कीर्ति व्यास, अनिल दास गुप्ता, श्रसंजय ठाकुर, प्रकाश यादव, श्रीमती इंदु अग्रवाल, श्रीमती श्रद्धा मिश्रा, श्रीमती दीक्षा गंगराड़े का स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर विधायक डोमन लाल कोर्सेवाड़ा ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में मेरा स्वाभाविक रूझान है। मैं अपने क्षेत्र में हमेशा दलित एवं शोषितों के लिए कार्य किया। मुझे एक बार सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। विधायक मोती लाल साहू ने कहा कि कई शालाओं में प्रवेश उत्सव के अवसर में शामिल हुआ वहां पर मैंने देखा सभी बच्चे उत्साह के साथ शाला में उपस्थित हो रहे थे इसी प्रकार शिक्षकगण अपना कार्य मन लगाकर करते हुए देखा।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.